सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 196 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 30 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

धमतरी में बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल, 500 सीट की क्षमता, मंत्रालय भेजा गया प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा : रायपुर संभाग का बनेगा प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में प्रदेश के सबसे बड़े सैनिक स्कूल के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां 500 सीटों की क्षमता वाला सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य स्तर से अनुमोदित होकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेषित कर दिया गया है। यह प्रस्ताव स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण पार कर चुका है और अब केंद्रीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया जारी है। प्रस्तावित सैनिक स्कूल के स्थापित होने पर धमतरी जिला न केवल रायपुर संभाग बल्कि पूरे प्रदेश में एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरेगा।

मिली जानकारी के अनुसार, यह सैनिक स्कूल रायपुर संभाग का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल होगा, जो आधुनिक सुविधाओं एवं उच्च स्तरीय अधोसंरचना से सुसज्जित रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा शीघ्र ही संभावित स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण उपरांत उपयुक्त स्थल का चयन कर आगे की औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा इस परियोजना को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। भूमि चयन, आवश्यक अधोसंरचना एवं अन्य व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है।

मिलेगी राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

सैनिक स्कूल की स्थापना से धमतरी जिले सहित आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। यहां छात्रों को अनुशासित वातावरण में शैक्षणिक, शारीरिक एवं नेतृत्व क्षमता के समग्र विकास का अवसर मिलेगा। यह संस्थान विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं। सैनिक स्कूलों के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) एवं अन्य प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु सुदृढ़ आधार मिलता है।

सैनिक स्कूल की स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी में 500 सीटर सैनिक स्कूल की स्थापना जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से प्रस्ताव स्वीकृत होकर रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। जिला प्रशासन इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है, ताकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि यह संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण एवं अनुशासित शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना को भी सुदृढ़ करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सैनिक स्कूल की स्थापना से धमतरी जिला शिक्षा के क्षेत्र में एक नए केंद्र के रूप में उभरेगा और यहां के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

खास-खबर

छत्तीसगढ़ में बिल्डर-कारोबारी के ठिकानों पर ईडी रेड

भिलाई। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने दुर्ग और बिलासपुर में रेड मारी है। दुर्ग में 'अमर इंफ्रा' के संचालक और भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के निवास व दफ्तर पर दबिश दी गई है, जहां टीम उनके आधा दर्जन फर्मों के वित्तीय दस्तावेजों और निवेश के रिकॉर्ड खंगाल रही है। दूसरी ओर, बिलासपुर में बड़े सर्राफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और सदर बाजार स्थित 'श्री राम ज्वेलर्स' पर ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारियों ने छापा मारा है। यह कार्रवाई शराब घोटाले के फरार आरोपी विकास अग्रवाल के सिंडिकेट से जुड़े तार खंगालने के लिए की जा रही है, जो अनवर ढेबर का करीबी और विवेक अग्रवाल का भाई बताया जा रहा है। बता दें कि राज्य में निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजा घोटाले में भाजपा-कांग्रेस के विधायक और दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इनकी भूमिका की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिन क्षेत्रों से यह प्रोजेक्ट गुजर रहा है, वहां दिग्गज नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदी। बाद में उन्हीं जमीनों का मुआवजा भी लिया।

छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में बने डीआईजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह ने हैदराबाद स्थित मुख्यालय में सीआईएसएफ साउथ जोन-2 के डीआईजी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इस पद के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक की सीआईएसएफ-संरक्षित इकाइयों जैसे खदान, कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा भी इनके अधीन होगी। इससे पहले आईपीएस संतोष सिंह छत्तीसगढ़ के कई चुनौतीपूर्ण जिलों में कप्तानी कर चुके हैं। विशेष रूप से रायपुर एसएसपी के रूप में उनके कार्यकाल को काफी सराहा गया था। वर्तमान में वे पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी जीतू सैनी मुठभेड़ में ढेर

बुलंदशहर। शहर के खुर्जा में सुभाष मार्ग स्थित जिम पर 25 अप्रैल की रात को हुए तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपीय जीतू सैनी और पुलिस के बीच बृहस्पतिवार सुबह सिकंदरपुर गांव के पास मुठभेड़ हुई। इसमें जीतू सैनी के दो गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में जटिया अस्पताल लाया गया। वहां से उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।अस्पताल में उपचार के दौरान जीतू सैनी की मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम प्रभारी मोहम्मद असलम और सिपाही मोहित मलिक के भी गोली लगी, जिनको जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम जीतू के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। इससे पहले, बुधवार को भी कोतवाली पुलिस और तिहरे हत्याकांड के दो आरोपी 50-50 हजार रुपए इनामी रिंकू व भारत के बीच मंगलवार रात को मुठभेड़ हुई थी।

आईपीएल मैच के लिए छत्तीसगढ़ी थीम पर सजाया जा रहा बॉक्स

रायपुर। आईपीएल के दो मुकाबले (10 और 13 मई) से पहले नया रायपुर का परसदा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट वेन्यू नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का ग्लोबल शोकेस बनने जा रहा है। स्टेडियम के 40 कॉर्पोरेट बॉक्स को छत्तीसगढ़ी थीम पर सजाया जा रहा है। 120 से अधिक देशों में जब मैच का सीधा प्रसारण होगा तो यहां की लोक कला, रंग और परंपरा भी दुनिया देखेगी। मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अधिकारी रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ फ्रेंचाइजी अगले तीन से चार दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टिकटिंग, एंट्री सिस्टम और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देगी। खास बात यह है कि इस बार एंट्री पूरी तरह डिजिटल होगी।

टॉप-10 में प्रयास स्कूलों के 13 छात्र, रायपुर के बड़े निजी स्कूलों को दिया टक्कर, शानदार रहा प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। इस वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश के 'प्रयास' आवासीय विद्यालयों ने शानदार सफलता हासिल किये हैं। यह न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मिसाल कायम की है। प्रयास विद्यालयों के 13 बच्चों ने सीजी बोर्ड परीक्षा के टॉप-10 में जगह बनाई है। प्रदेश के 50 मेरिट छात्रों में से 13 विद्यार्थी प्रयास विद्यालय के हैं।

छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की ओर से संचालित इन स्कूलों में सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के

बावजूद इन विद्यालयों के छात्रों ने शानदार परिणाम देते हुए बड़े निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दी है। हायर सेकेंडरी परीक्षा (कक्षा 12वीं) में प्रयास आवासीय विद्यालय के कुल 128 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कुल 17 प्रयास विद्यालय संचालित है। जिसमें नक्सल प्रभावित बच्चों से लेकर सभी वर्गों के बच्चें अध्ययनरत है।

सीएम साय ने दी बधाई

प्रयास विद्यालय के इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सफ्ऊलता प्रयास आवासीय विद्यालयों की अवधारणा की सार्थकता को प्रमाणित करती है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए गए सतत प्रयास की सराहना की हैं। प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की यह उपलब्धि राज्य के लिए गौरव का विषय है तथा यह अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्त्रोत सिद्ध होगी।

छत्तीसगढ़ में तेंदुए का शिकार कर मांस पकाकर खा गए बदमाश, खाल बेचने निकले और पकड़ाए

ग्राहक बनकर पहुंची फॉरेस्ट की टीम, खाल सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 5 शिकारियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने पहले तेंदुए को फंदे में फंसाया, फिर उसे जिंदा हालत में कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर मार दिया। जिसके बाद खाल निकाल ली और मांस को खा गए। खाल बेचने की फिराक में थे।

जानकारी के मुताबिक, ये मामला गीदम रेंज के गुमलनार इलाके का है। वन विभाग की टीम को तेंदुए का शिकार और खाल बेचने वाले हैं इसकी जानकारी मिली थी। जिसके बाद छ्स्न्ह्र रंगनाधा रामाकृष्णा वाय के निर्देश पर बचेली रेंजर डॉ प्रीतेश पांडेय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इस

टीम ने शिकारियों को पकड़ने जाल बिछाया।अधिकारी-कर्मचारी खुद ग्राहक बने। वहीं खाल का सौदा करने पहुंचे शिकारियों को पकड़ लिया। इन्होंने अपना नाम सुंदरलाल, धरमू सिमरथ, दियालू, दिनेश कश्यप और गोबरु बताया। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इनके पास से तेंदुए की खाल बरामद की है। तेंदुए की उम्र करीब 6 से 7 साल थी।

जानिए कैसे किया शिकार

वन्यजीव पानी की तलाश में नदी किनारे आते हैं। शिकारियों नदी किनारे फंदा लगाकर रखा था जिसमें तेंदुआ फंस गया। शिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तेंदुए के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसे मार दिए। जिसके बाद खाल निकाल ली।

वन्यजीव अनमोल, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा

रेंजर डॉ प्रीतेश पांडे ने कहा कि वन्यजीवों का शिकार गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तेंदुए जैसे जीव अनमोल हैं और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गैस सिलिंडर लीकेज से भड़की आग एक ही परिवार के सात लोग झुलसे

भिवाड़ी। के साथलका गांव स्थित बिल्लू लेबर कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में हुए लीकेज के चलते अचानक भीषण आग भड़क उठी, जिसमें एक ही परिवार के सात लोग बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश निवासी 35 वर्षीय नेम सिंह अपने परिवार के साथ कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहा था। सुबह वह खाना बनाने के दौरान गैस सिलिंडर बदल रहा था। इसी दौरान नए सिलिंडर से गैस का रिसाव होने लगा। कुछ ही पलों में कमरे में एलपीजी गैस फैल गई और आग के संपर्क में आते ही तेज धमाके के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में नेम सिंह, उनकी पत्नी ममता (30), मामा बृजेश (32) और चार बच्चे पंकज (8), छगन (6), काजल (15) और किशनबती (12) आग की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, खासतौर पर बच्चों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

कच्चे तेल में भारी उछाल: ब्रेंट क्रूड 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी तेजी दर्ज की गई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल उछलकर 120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में गतिरोध और ईरानी बंदरगाहों व निर्यात पर अमेरिका की लंबी नाकेबंदी की चिंताओं के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से यह भारी उछाल आया है।

इस ऊर्जा संकट के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक प्रमुख कारण है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की पेशकश की गई थी; ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि जब तक कोई व्यापक परमाणु समझौता नहीं हो जाता, तब तक रोक जारी रहेगी। नाकेबंदी के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए ट्रंप ने तेल कंपनियों के साथ बैठक भी की है।

इसके साथ ही, ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जल्द समझदारी दिखानी चाहिए। इस पोस्ट में एक एआई-जनरेटेड तस्वीर भी साझा की गई, जिसमें ट्रंप को बंदूक पकड़े हुए दिखाया गया है और पीछे विस्फोट हो रहे हैं, साथ ही नो मोर मिस्टर नाइस गाय! का संदेश लिखा गया है। विश्लेषकों ने इस स्थिति को दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा व्यवधान बताया है।

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल रायपुर बेंच का काम शुरू, कर संबंधि समस्याओं का होगा समाधान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के करदाताओं और संबंधित हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) की रायपुर बेंच ने अपना कामकाज प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी करदाताओं, विभागीय अधिकारियों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है।

रायपुर बेंच का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन के नॉर्थ बी-ब्लॉक, सेक्टर-19 में स्थापित किया गया है। यह बेंच सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 तथा संबंधित राज्य

जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करेगी। जारी सूचना के अनुसार, अब छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी अपीलें, आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियां इसी बेंच के समक्ष दायर की जाएंगी। इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम, 2025 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश, ई-फाइलिंग एडवाइजरी एवं अन्य आदेश त्रस्ञ्जञ्ज के आधिकारिक पोर्टल पर "Notice" सेक्शन में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, ई-फाइलिंग के दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर अपीलकर्ता टोल- फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन 'इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म' के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सार्वजनिक सूचना जनहित में जारी की गई है, जिसका उद्देश्य करदाताओं और विभागीय प्राधिकारियों को रायपुर बेंच की स्थापना और उसके कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्रदान करना है।

दुर्ग ट्रिपल मर्डर केस, पत्नी-बेटी को जिंदा जलाया मानसिक रोगी का गला घोंटा, कोर्ट ने दी फांसी

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में दुर्ग कोर्ट ने 6 साल बाद आरोपी रवि शर्मा को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 का है, जिसमें आरोपी ने अपनी पत्नी और डेढ़ साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी थी। उस पर किसी को शक न हो इसके लिए उसने एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी मार दिया, ताकि वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके।

जांच में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी और बच्चे राउरकेला में रहते हैं। भिलाई में उसने मंजू से दूसरी शादी कर ली थी। मंजू ने डेढ़

महीने पहले बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन रवि इस बच्चे को नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। आखिरकार तंग आकर उसने मंजू को मारने की योजना बना ली। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर पता लगा लिया था कि तीनों मर्डर के पीछे रवि शर्मा का ही हाथ था।

जांच के दौरान मिले कई अहम सबूत

जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल्स, इस्तेमाल किए गए सामान और दवाइयों की जांच, सीसीटीवी फुज और गवाहों के बयान जैसे अहम सबूत सामने आए। इन सभी सबूतों के आधार पर दुर्ग कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी को हत्याकांड के लिए मौत की सजा सुनाई। इस मामले में दुर्ग न्यायालय में शासकीय वकील भावेश कटरे ने पैरवी की। भिलाई नगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रुव ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

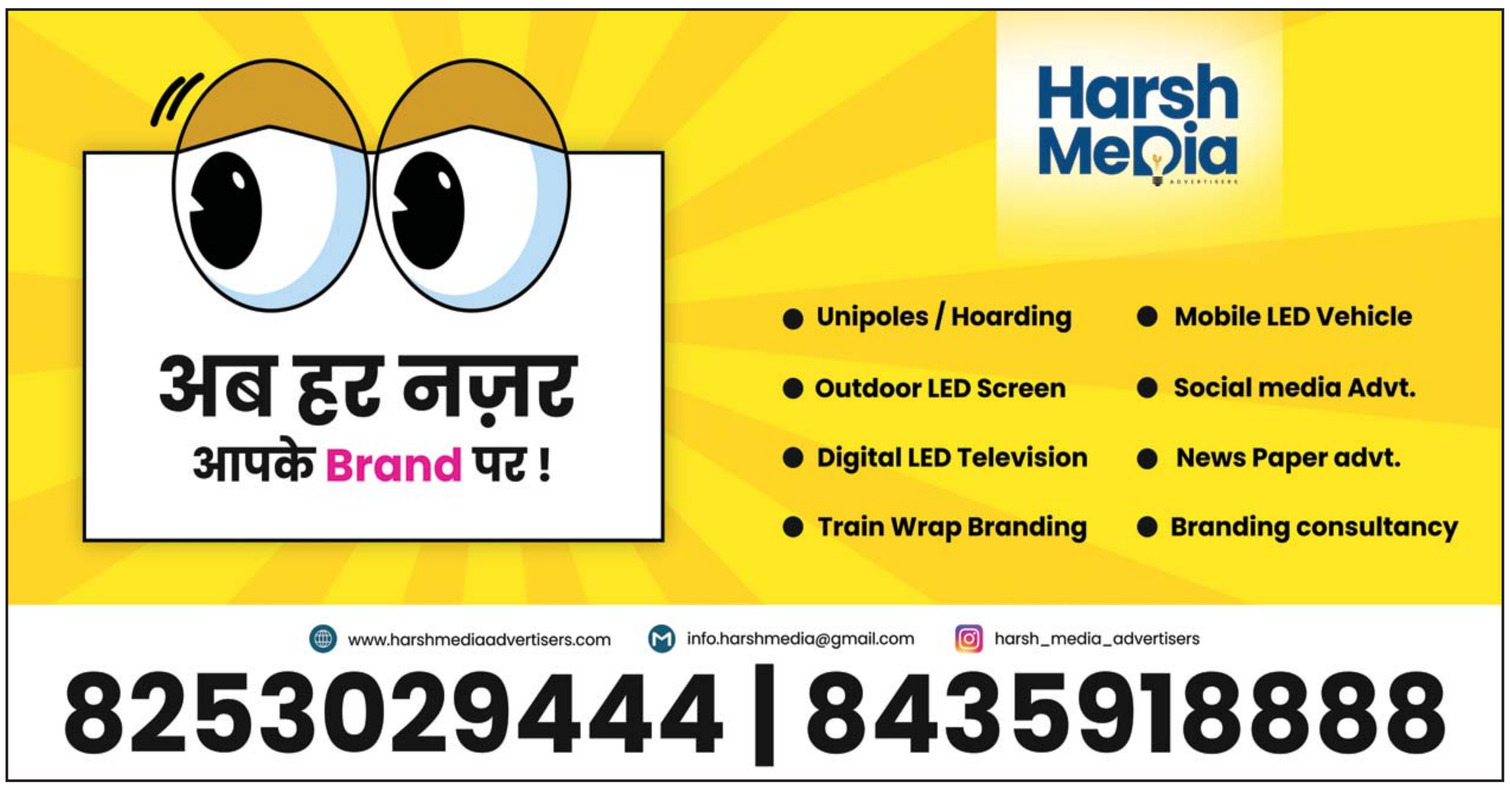

संपादकीय

राहतकारी हो आईसीयू

गहन चिकित्सा देखभाल के संवेदनशील दिशानिर्देश

अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि देश के किसी भाग में किसी निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के ठीक होने या ठीक होने की संभावना के बावजूद उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। वजह होती है कि अस्पताल का अनवरत गति से चलने वाला कमाई का मीटर। निस्संदेह, आधुनिक चिकित्सा खर्चीली हो गई और बेहतर सुविधाओं के लिए बड़ी रकम चुकानी होती है। लेकिन इस व्यवस्था का मानवीय व संवेदनशील होना अपरिहार्य है। इसके नियमन का कार्य यूं तो देश के नीति-नियंताओं और शासन-प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत को ऐसे मामलों में पहल करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान गहन चिकित्सा ईकाई दिशानिर्देशों की जरूरत बताना विसंगतियों से जूझती आईसीयू प्रणाली के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। इन दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य सामान्य वार्डों में स्थानांतरित किया जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायालय के ये निर्देश चिकित्सकीय और नैतिक दोनों ही हैं। जो बताते हैं कि जरूरी न होने के बावजूद मरीज को लंबे समय तक आईसीयू में रखना अनुचित है। यह एक हकीकत है कि मानकीकृत आईसीयू प्रोटोकॉल के अभाव में एक अस्पष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज से जुड़े निर्णय असमंजस का शिकार होकर रह जाते हैं। वास्तव में आईसीयू में भर्ती मरीजों के तिमारदारों को चिकित्सा प्रक्रिया की गहन जानकारी अक्सर नहीं होती है। वे केवल चिकित्सक के दिशा-निर्देशों पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन के रहमो-करम पर मरीज को महंगे आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती रहने के बावजूद मरीज को उपचारीय लाभ नहीं मिल रहा होता है। सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश एक सरल व सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अस्पताल का आईसीयू मरीज की अनिश्चितकालीन देखभाल के लिए नहीं होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने समस्या के यथाशीघ्र समाधान की जरूरत पर बल दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को संरक्षित करते हुए चिकित्सा संस्थानों व अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इस दिशा में व्यवस्थागत मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें नर्स व मरीज के अनुपात, विशेषज्ञ पर्यवेक्षण, मानक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कराना एक सराहनीय पहल कही जाएगी। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में भारी असमानता है, ये न्यूनतम मानदंड अधिक न्यायसंगत देखभाल के लिए आधार बन सकते हैं। सही मायनों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही निर्देश नीति के क्रियान्वयन हेतु तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन विगत के अनुभव बताते हैं कि एक अच्छे इरादे वाली कार्ययोजना तब अपने लक्ष्य पाने में विफल हो जाती हैं जब उसका क्रियान्वयन आधे-अधूरे ढंग से किया जाता रहा है। निश्चित रूप से निगरानी ढांचे और समन्वित राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई पर अदालत की पहल सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी अनुपालन की सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्त पोषण और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगी। साथ ही दक्षता के अलावा, मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गहन चिकित्सा कक्ष में लंबे समय तक भर्ती रहना मरीजों और उनके परिवारों के लिए बेहद कष्टदायक होता है। स्थिर मरीजों को कम स्तर पर देखभाल की जरूरत वाले वार्डों में स्थानांतरित किए जाने से न केवल अनावश्यक चिकित्सा खर्च बचता है। बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण का भी परिचायक है। निश्चित रूप से आईसीयू के लिए एकसमान मानदंड लागू करने का प्रयास भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।

"इन दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य सामान्य वार्डों में स्थानांतरित किया जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायालय के ये निर्देश चिकित्सकीय और नैतिक दोनों ही हैं। जो बताते हैं कि जरूरी न होने के बावजूद मरीज को लंबे समय तक आईसीयू में रखना अनुचित है। यह एक हकीकत है कि मानकीकृत आईसीयू प्रोटोकॉल के अभाव में एक अस्पष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज से जुड़े निर्णय असमंजस का शिकार होकर रह जाते हैं। वास्तव में आईसीयू में भर्ती मरीजों के तिमारदारों को चिकित्सा प्रक्रिया की गहन जानकारी अक्सर नहीं होती है।

नए ज़िम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का निर्माण

श्री एस. कृष्णन

ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करने की दिशा में भारत की पहल अवसर और जोखिम के संगम से उत्पन्न हुई है। बीते एक दशक में डिजिटल गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसे बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन अपनाने, किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीक का उपयोग करने और उस पर निर्भर रहने वाली युवा आबादी का समर्थन मिला है। इस विकास ने नवाचार, कौशल विकास, रचनात्मक उद्योगों और रोजगार सृजन के लिए सार्थक अवसरों का सृजन किया है। मनोविनोद के लिए गेमिंग और संगठित प्रतिस्पर्धी प्रारूपों ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता भी प्रदर्शित की है।

इन अवसरों के साथ-साथ, ऑनलाइन मनी गेमिंग—विशेष रूप से सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले (यानी बेटिंग वेजरिंग) प्लेटफॉर्मों के अनियंत्रित विस्तार ने गंभीर सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को भी जन्म दिया। ऐसे अनेक सेवा प्रदाता राज्य सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्रों से संचालित होते थे, जो घरेलू सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज़ करते थे और कानूनों को लागू करना कठिन बनाते थे। दबाव बनाने वाले विज्ञापनों और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाले डिज़ाइन फीचर्स ने कमजोर उपयोगकर्ताओं में लत जैसी प्रवृत्तियों और वित्तीय नुकसान को बढ़ावा दिया। वित्तीय संकट, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के दुरुपयोग और अस्पष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन की रिपोर्ट्स ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को उजागर किया। इन परिस्थितियों ने एक ऐसे राष्ट्रीय ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो व्यक्तियों—विशेषकर युवाओं—की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गेमिंग इकोसिस्टम के वैध हिस्सों को जिम्मेदारी से विकसित होने में सक्षम बनाए।

ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स नामक संगठित प्रतिस्पर्धी प्रारूपों जैसे वैध गेमिंग क्षेत्रों की सहायता के लिए एकीकृत संस्थागत ढाँचे का अभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। डेवलपर्स के पास श्रेणीकरण की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, जिसका पहले से अनुमान लगाया जा सके और उपयोगकर्ताओं को अक्सर वैध मनोरंजन और अवैध सट्टेबाजी के बीच फर्क समझने में कठिनाई होती थी। अतः इसका उद्देश्य केवल हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि एक संतुलित ढाँचा भी स्थापित करना था, जो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जिम्मेदार नवाचार को भी संभव बनाए। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025, (पीआरओजीए) इसी संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे डेवलपर्स, ई-स्पोर्ट्स संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी पेशेवरों और सामाजिक संगठनों के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं में लगातार पारदर्शी श्रेणीकरण, पूर्वानुमेय अनुपालन दायित्वों और वैध प्रारूपों के लिए व्यवस्थित व सरल मान्यता प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हितधारकों ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई मजबूत करते हुए वैध मनोरंजक और प्रतिस्पर्धी गेमिंग को बढ़ावा देने का समर्थन किया। संचालन स्तर पर, यह ढाँचा परस्पर संबद्ध तीन चरणों—अवधारण, मान्यता और पंजीकरण—पर आधारित एक व्यवस्थित श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये चरण क्रमिक रूप से कार्य करते हैं और इन्हें पीआरओजीए तथा उसके नियमों में दी गई वैधानिक परिभाषाओं के साथ समझना आवश्यक है।

अवधारण एक नियामक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से किसी भी गेम की जांच और उसका श्रेणीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक ऑनलाइन गेम के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल सीमित और निर्धारित परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-स्पोर्ट्स की मान्यता से पहले अवधारण अनिवार्य होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्धी प्रारूप वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और सट्टेबाजी के तत्वों से मुक्त रहते हैं। इसके अलावा, अवधारण आमतौर पर उन स्थितियों में आवश्यक होता है, जब किसी गेम के ऑनलाइन मनी गेमिंग की परिभाषा के दायरे में आने की आशंका हो, जब अधिसूचित ऑनलाइन सोशल गेम्स की श्रेणियों के लिए श्रेणीकरण जरूरी हो, जब शिकायतों या खुफिया सूचनाओं से प्रतिबंधित गतिविधियों को सक्षम करने वाले संभावित वित्तीय तत्वों का संकेत मिले, या जब भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआई) जनहित में जांच का निर्देश दे। अवधारण प्रारंभिक श्रेणीकरण को संभव बनाकर, अवैध वित्तीय मॉडलों को गेमिंग इकोसिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है, जबकि वैध प्रारूपों को नियामक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

अवधारण के बाद, पात्र प्रारूपों को मान्यता दी जा सकती है। ई-स्पोर्ट्स की मान्यता राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत विनियमित होती है, जिसमें संगठित मल्टीप्लेयर गेमप्ले, पूर्व-निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक नियम और परिणाम केवल मानसिक कौशल, शारीरिक दक्षता या रणनीतिक निर्णय लेने जैसे कारकों पर आधारित होना आवश्यक है। प्रतिभागिता शुल्क की अनुमति केवल प्रतियोगिता से संबंधित प्रशासनिक खर्चों और प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार संरचनाओं को समर्थन देने के लिए ही दी जा सकती है। हालांकि, किसी भी रूप में सट्टेबाजी या दांव लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। मान्यता से पहले अनिवार्य अवधारण यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त ई-स्पोर्ट्स प्रारूप सभी वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। इसके समानांतर, यह ढाँचा ऑनलाइन सोशल गेम्स के पंजीकरण के लिए एक मार्ग स्थापित करता है, जो वित्तीय सट्टेबाजी के लिए नहीं, बल्कि मुख्यतः मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता के उद्देश्य से बनाए गए होते हैं। ऑनलाइन सोशल गेम्स की केवल उन्हीं श्रेणियों का ही पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो। जहाँ श्रेणीकरण की निश्चितता होना आवश्यक है, वहाँ पंजीकरण से पहले अवधारण किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें सट्टेबाजी के तत्व मौजूद नहीं हैं। इस श्रृंखला का अंतिम चरण पंजीकरण है, जो नियामक दृश्यता प्रदान करता है तथा संतुलित निगरानी और लागू की जा सकने वाली जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पंजीकरण आमतौर पर ई-स्पोर्ट्स की मान्यता के बाद होता है या फिर ऑनलाइन सोशल गेम्स की अधिसूचित श्रेणियों पर लागू होता है। यह उन मामलों में भी निर्देशित किया जा सकता है, जहाँ निर्धारण के परिणाम औपचारिक निगरानी की आवश्यकता दर्शाते हैं या जहाँ ओजीएआई जनहित में ऐसी निगरानी को आवश्यक समझता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण पूरे प्लेटफॉर्म पर नहीं ,बल्कि प्रत्येक ऑनलाइन गेम सेवा प्रदाता के अलग-अलग खेलों पर लागू होता है, जिससे अनुपालन यथोचित बना रहता है और साथ ही प्राधिकरणों को अधिकृत खेलों का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह वर्तमान ढाँचा प्रतिक्रियात्मक प्रवर्तन से आगे बढ़कर सक्रिय और निवारक शासन की ओर परिवर्तन दर्शाता है। अनुकूल अवधारण प्रारंभिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, मान्यता वैधता का स्पष्ट फर्क स्थापित करती है, और पंजीकरण नियामक दृश्यता प्रदान करते हुए सही निगरानी और लागू की जा सकने वाली जवाबदेही सुनिश्चित करता है। साथ ही, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ कार्यान्वयन को, विशेष रूप से विदेशी ऑपरेटरों को लक्षित करते हुए समन्वित ब्लॉकिंग, जांच-आधारित ओजीएआई की कार्रवाई और वित्तीय व्यवधान के उपायों के माध्यम से मजबूत किया गया है। यह दो-स्तरीय दृष्टिकोण ढाँचे की मूल विचारधाराः वैध संस्थाओं के लिए हल्के फुल्के नियमन तथा अवैध संचालकों के खिलाफसख्त कार्यान्वयन को प्रतिबिंबित करता है।

कार्यान्वयन के अलावा, यह ढाँचा जिम्मेदार इकोसिस्टम के विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करता है। स्पष्ट नियामक मार्ग वैध गेमिंग के विकास, प्रतिस्पर्धी अवसंरचना और सहायक डिजिटल सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। ई-स्पोर्ट्स की मान्यता संगठित प्रतियोगिताओं और पेशेवर भागीदारी को सक्षम बनाती है, जबकि विनियमित श्रेणियाँ विकास, अनुपालन, साइबर सुरक्षा और इवेंट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों में सहायता देती हैं। पीआरओजीए के माध्यम से शुरू किया गया यह परिवर्तन बिखरी हुई प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर पूर्वानुमेय शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है। निवारक श्रेणीकरण, वैध मान्यता और जवाबदेह पंजीकरण को एक साथ जोड़कर यह ढाँचा एक स्थिर वातावरण तैयार करता है, जहाँ नवाचार जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदारी के साथ विकसित हो सकता है।

लेखक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं।

किसी के लिए उम्मीद ही सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है

एन. रघुरामन

सुगि अमाया (29) की कहानी किसी बड़े अभियान से नहीं, बल्कि एक सन्नाटे के साथ शुरू हुई। जुलाई 2022 में उनका संसार बिखर गया, जब उनके 24 साल के भाई एलेक्सिस को पापा जॉन्स पिज्जेरिया से लेट-नाइट शिफ्ट करके लौटते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप एल-साल्वाडोर का वही जाना-पहचाना था- गैंग से जुड़ाव। किसी ट्रायल और कानूनी रास्ते के बगैर ही एलेक्सिस को वो जेल सिस्टम निगल गया, जो पूरे देश के लिए पुलिसिया जाल बन चुका था।

यह सेंट्रल अमेरिका के सबसे छोटे देश एल-साल्वाडोर की हकीकत है। 2022 की शुरुआत में हत्याओं में तेज बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने आपातकाल लगा दिया। जो कदम अपराध के खिलाफ शुरू हुआ, धीरे-धीरे ऐतिहासिक सख्ती में बदल गया। आज इस देश में दुनिया की सर्वाधिक कारावास दर है, जहां कार्रवाई की शुरुआत से अब तक 91 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह वयस्क आबादी का करीब 2% है। मानवाधिकार संगठनों ने चेताया है कि 'अरेस्ट कोटा' के चलते पुलिस गरीबों को निशाना बना रही है। एलेक्सिस जैसे लोगों को अकसर सिर्फ टैटू या अनजान सूचना के आधार पर पकड़ लिया जाता है। नतीजतन, इस देश में बहुत बड़ा विरोधाभास है। आंकड़ों में तो एल-साल्वाडोर दुनिया के सबसे हिंसक देशों में से एक से बदलकर पश्चिमी गोलार्ध के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हो गया। लोग नई आजादी की बात करते हैं- मसलन, रात में बेखौफचल पाना या बिना वसूली के दुकान चला पाना। लेकिन इस सुरक्षा की भयानक कीमत पीछे छूट गए परिवारों को चुकानी पड़ी है। बुनियादी सुविधाओं की किल्लत वाली और भीड़ भरी जेलों में बंद रिश्तेदारों के लिए खाना और दवाएं जुटाना गरीबों के जीवन का संघर्ष बन गया है। एलेक्सिस की गिरफ्तारी के बाद सुगि का जीवन राजधानी सैन-साल्वाडोर के एक कन्वर्टेड मूवी थिएटर के बाहर के फर्श तक सिमट गया है। यह जगह जटिल जेल सिस्टम में आने-जाने वालों के लिए ठहराव स्थल है। जेल की दीवारों की छांव अब सुगि का दूसरा घर बन गई है। भाई की गैरमौजूदगी की इस रिक्तता में कड़वाहट उनके मन में आ सकती थी। लोहे के इन दरवाजों में उन्हें सिर्फ दुश्मन ही दिख सकते थे। लेकिन उन्होंने इनमें एक आईना देखना चुना।

बच्चों को अपनी मां के पास छोड़कर सुगि रात भर इंतजार करती हैं। एल-साल्वाडोर में कैदियों की रिहाई बहुत कम और अकसर बिना सूचना के तड़के ही होती है। तब कोई रिश्तेदार कागजों पर साइन करने के लिए न हो तो कैदी वापस भीतर भेज दिया जाता है। इसे रोकने के लिए सुगि अजनबियों के लिए वहां रहती हैं।

वह बिना किसी सोच-विचार के एक साफ शर्ट और जूते लेकर रिहा हुए लोगों के पास जाती हैं और रिलीज फॉर्म पर साइन करती हैं। धीरे से कहती हैं, 'अब आप ठीक हैं।' सुगि की आवाज उन्हें फिर से जिंदगी से जोड़ती है। जरूरतमंदों को वह घर जाने का किराया देती हैं और जिनके पास कोई जगह नहीं, सुगि का छोटा-सा घर ही ठिकाना होता है- जहां गर्म खाने और बिस्तर से उनका 'क्रिमिनल' का टैग धुल जाता है।

जब लोग पूछते हैं कि वे अनजान लोगों के लिए क्यों गंदगी में रातें बिताती हैं, तो सुगि को एलेक्सिस याद आता है। उनकी उम्मीद किसी चक्र जैसी है। उन्हें भरोसा है कि अजनबियों के साथ सम्मान से पेश आकर वे दुनिया में इतनी रोशनी फैला रही हैं, जो उस अंधेरी कोठरी तक पहुंचेगी, जहां उनका भाई है।

वे ऐसी दुनिया बना रही हैं, जिसमें वे चाहती हैं कि उनका भाई लौटे। आज सुगि का मिशन बढ़ चुका है। पूरे अमेरिका महाद्वीप से परिवार उन्हें मदद भेजते हैं। जिनकी उन्होंने मदद की थी, वे इसमें योगदान दे रहे हैं। अब वे कानून की छात्रा हैं, लेकिन उनका 'फुल-टाइम जॉब' दूसरों के लिए जेल सिस्टम से जूझना ही है।

फंडा यह है कि अजनबियों को बचाने के इस काम में सुगि ने खुद को निराशा से बचा लिया और साबित किया कि उम्मीद बांटी जाए तो यह सबसे ताकतवर तोहफा बन जाती है।

घर-बाहर के दबाव में तनाव झेलती महिलाएं

दीपिका अरोरा

शोध के मुताबिक़, 72.2 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं उच्च तनाव में हैं, जो पुरुषों (53.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 90 प्रतिशत महिलाएं यद्यपि मानती हैं कि स्वास्थ्य मुद्दे उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, तथापि भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण वे मदद मांगने से झिझकती हैं।

'मल्टीटॉस्किंग' एक नैसर्गिक गुण है, महिलाएं जिसमें विशेष रूप से माहिर मानी गई हैं। यूं भी अधिकतर भारतीय परिवारों में घरेलू कार्य स्त्रियों के ही हवाले रहते हैं, भले ही वह अतिरिक्त भार उठाने में सक्षम हो अथवा न। परंपरागत समाज के लिए यह आम बात हो सकती है किंतु परिवर्तित परिदृश्य में दोहरे दायित्व का निर्वहन कहीं न कहीं नारी-स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। हेल्थ स्टार्टअप त्राया द्वारा भारत के 15 राज्यों की 5,35,373 महिलाओं पर किया नवीनतम सर्वेक्षण देश में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं के प्रतिदिन क्रॉनिक स्ट्रेस झेलने का खुलासा करता है। पश्चिम बंगाल में 52.2 प्रतिशत महिलाएं तनाव की शिकार हैं, तमिलनाडु एवं दिल्ली में यह आंकड़ा क्रमशः 50.5 तथा 47.8 प्रतिशत है। सर्वाधिक चिंताजनक है, तनाव की कोई आकस्मिक घटना न होकर निरंतर चलने वाली समस्या बनना, जो कि नींद से लेकर महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य तक को चपेट में ले रही है। सर्वे के निष्कर्ष बताते हैं कि कार्य तथा व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन, कार्यस्थल पर होने

वाला भेदभाव, आर्थिक दबाव तथा सामाजिक अपेक्षाओं के फलस्वरूप उपजते तनाव से महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताएं बहुतेरे प्रभावित हो रही हैं। लगभग 5 में से 2 महिलाएं पर्याप्त निद्रा नहीं ले पा रहीं, वहीं हर 2 में से 1 महिला पेट तथा पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, असल में ये सभी दिक्कतें अलग-अलग न होकर परस्पर जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर यह उसी तनाव के परिणाम हैं, जिसे महिलाएं नित्यप्रति ढो रही हैं। विशेषज्ञों की मानें तो, पारिवारिक-सामाजिक भूमिका के तहत महिलाओं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने वाली पारंपरिक सोच तथा आधुनिक जीवनशैली के आपसी द्वंद्व ने समस्या और गहरा दी है। शोध के मुताबिक़, 72.2 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं उच्च तनाव में हैं, जो पुरुषों (53.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 90 प्रतिशत महिलाएं यद्यपि मानती हैं कि स्वास्थ्य मुद्दे उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, तथापि भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण वे मदद मांगने से झिझकती हैं। इसका एक बड़ा कारण आज भी व्यापक स्तर पर व्याप्त लिंगभेद है। सर्वे यह भी बताता है कि महिलाओं से लगातार ज़्यादा काम की उम्मीद पालने वाली संकीर्ण सोच में यह कम ही पूछा जाता है कि क्या उनके पास इसे निभाने के लिए ज़रूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बची भी है या नहीं घर-कार्यस्थल में सामंजस्य बिठाने का प्रयास एवं प्रत्येक कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की चाह तनाव के रूप में उभरकर उदासी, अवसाद, चिड़चिड़ेपन आदि अनेकानेक व्याधियों की उत्पत्ति का निमित्त बन रही है। दुर्भाग्य से आज भी भारतीय समाज में मानसिक रोगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता।

महिलाओं के संदर्भ में तो स्थिति विशेषकर निराशाजनक है। उनके स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक दायित्व अथवा सामाजिक जागरूकता के बारे तथ्य खंगालें तो सर्वे के मुताबिक़, अधिकांश मामलों में महिलाओं की भावनाओं एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जिस कारण तनाव, चिंता गहरे अवसाद में परिणत होने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी जटिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, साक्षरता का अभाव, निर्धनता तथा अंधविश्वासी प्रवृत्ति के चलते मानसिक रोगों को भूत-प्रेत की छाया अथवा जादू-टोने का प्रभाव मान लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरी मदद लेने की बजाय ओझा, तांत्रिक या झाड़-फूंक करने वालों को तरजीह दी जाती है, जो महिलाओं की हालत को और बिगाड़ देते हैं।

कई मामलों में मौत तक हो जाती है। अपनी सेहत की अनदेखी करने में महिलाएं भी कम दोषी नहीं। आमतौर पर स्त्रीवर्ग अपना ध्यान रखने अथवा क्षमता के अनुरूप कार्य करने की बजाय दूसरों की ज़रूरतों को अधिक अधिमान देता है। सबका ख़्याल रखना निस्संदेह, एक सराहनीय गुण है, किंतु कर्तव्य-पालन के अतिरेक में यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि 'सबका' शब्द में महिलाएं ख़ुद भी शामिल हैं। तनाव ढोती महिलाओं की चुप्पी कालांतर में स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इससे पूर्व कि तनाव जीवन को अस्त-व्यस्त कर डाले, काउंसलिंग करना अनिवार्य हो जाता है।

असल में, नर-नारी, परिवार तथा समाज रूपी गाड़ी चलाने वाले दो पहिए हैं। किसी भी पहिए पर क्षमता से अधिक बोझ लादना उसे क्षतिग्रस्त बना छोड़ेगा। देश की आधी आबादी का स्थाई तौर पर तनाव से जूझना मात्र स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा न होकर समग्र रूप में एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है। मानवीय आधार पर समझना होगा कि महिलाओं की भावनात्मक ज़रूरतें भी पुरुषों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अनदेखा करना सरासर अन्याय है।

डॉक्टरों के कथनानुसार, दीर्घकालीन तनाव के प्रति बरती गई कोताही भविष्य में असाध्य रोग बन सकती है। भीतर ही भीतर घुटने की अपेक्षा क्यों न परिजनों को शिष्टतापूर्वक अपनी मनोस्थिति से अवगत करवाया जाए ताकि समय रहते समुचित समाधान मिल सके? इसके लिए समाज, परिवार तथा सरकार को मिलकर एक ऐसा माहौल सृजित करना होगा, जहां महिलाएं निःसंकोच अपनी समस्याएं साझा कर सकें। मिल-बांटकर काम करने से जहां कार्यभार घटेगा, वहीं रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी; तनावरहित नारी अधिक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा स्वस्थ जीवन जी पाएगी।

ITR फाइल 500/-

Whatsapp पर बनवाएँ

Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस

हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।

www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ

भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

एसआईओ के वार्षिक छात्र सम्मेलन की तैयारी शुरू, पोस्टर लांच

भिलाई। नौजवानों को समाज निर्माण के लिए तैयार करने वाले छात्र संगठन एस.आई.ओ, छत्तीसगढ़ ने अपने वार्षिक छात्र सम्मेलन का ऐलान कर दिया है। यह सम्मेलन 11–12 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी सिलसिले में 26 अप्रैल को एस. आई. ओ भिलाई इकाई में आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया गया। जिसमें दिल्ली से आए मुख्य अतिथि एडवोकेट अनीस रहमान ने कहा कि समाज में बदलाव तब नज़र आता है जब हम उस बदलाव की शुरुआत खुद से करते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि एक बेहतर समाज बनाने में सभी का योगदान हो। इस मौके पर एसआईओ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अनस खान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता सभी छात्रों को साथ लेकर शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य करते हुए सामाजिक चुनौतियों को लेकर आवाज़ बुलंद करने की है। पोस्टर लॉन्च करते वक़्त मुख्य अतिथि एडवोकेट अनीस रहमान (महासचिव, एस.आई.ओ, इंडिया), एम डी ज़ुल्करनैन (मीडिया सचिव, एस आई ओ, छत्तीसगढ़), रयान खान (सलाहकार परिषद सदस्य), आमिर खान (सलाहकार परिषद सदस्य), शोएब अली (परिषद सदस्य), इदरीस खान (आयोजन सचिव), अब्दुल अहद फ्लाही (रायपुर इकाई अध्यक्ष) तथा कार्यकर्ता आदिल सिद्दिकी, अय्यूब खान, जैद अली, इमरान अज़ीज़, एवं अन्य कार्यकता मौजूद थे।

संजय को क्षत्रिय महासभा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट और स्टील अथॉरिटी ऑफइंडिया लिमिटेड (सेल) में उच्च पदस्थ रहे वरिष्ठ गायक–संगीतकार संजय सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन चंडीगढ़ में 11 एवं 12 अप्रैल को हुआ। जिसमें क्षत्रिय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। अधिवेशन के दौरान मथुरा से तीन बार सांसद रह चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजा मानवेन्द्र सिंह ने युवराज ऋषिराज सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही टिक्का शिवेंद्र पाल कुटलैहड़ को यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंदु तोमर को महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा घोषित किया गया। वहीं संजय सिंह को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर देश भर से 24 प्रांतों के पदाधिकारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। उल्लेखनीय है कि संजय सिंह एक प्रसिद्ध गायक हैं और भारतीय टेलीविजन के कई लोकप्रिय रियलिटी शोज़—जैसे सोनी टीवी, ज़ी टीवी और दूरदर्शन—के विजेता रह चुके हैं।

देश में पहली पहल: दुर्ग का जेंडर बैलेंस्ड सिस्टम बना रोल मॉडल

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे में रिश्तों की जटिलताएं भी नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही हैं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर पनपने वाली पीड़ा—चाहे वह किसी बुजुर्ग की उपेक्षा हो या किसी पुरुष का मानसिक तनाव—अनसुनी रह जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग ने इस खामोशी को आवाज़ देने का एक नया रास्ता दिखाया है। दुर्ग जिले में शुरू हुई जेंडर–बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था आज पारिवारिक विवाद समाधान का एक ऐसा समावेशी मॉडल बनकर उभरी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है।

सेक्टर–6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले मुख्यत: महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब एक व्यापक सामाजिक मंच बन चुका है। यहां महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जा रहा है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शुरू हुआ यह केंद्र समय के साथ अपने दायरे का विस्तार करता गया। बदलते पारिवारिक समीकरणों और विवादों के नए स्वरूप को देखते हुए इसमें जेंडर–बैलेंस्ड काउंसलिंग को लागू किया गया, जिससे हर पक्ष को निष्पक्ष और संतुलित सुनवाई का अवसर मिल सके।

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है—पुरुष काउंसलर की नियुक्ति। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक तनाव से जूझते हुए परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी बात को समझने और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद प्रभावी साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को समय की मांग बताते हुए कहा है कि काउंसलिंग आधारित समाधान से विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिससे परिवारों में सामंजस्य और सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। वहीं दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार, संवाद और परामर्श की प्रक्रिया पति–पत्नी के बीच बढ़ते विवादों को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोकने में कारगर साबित हो रही है। यह मॉडल न केवल विवादों को कम कर रहा है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रहा है।

इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है—'सीनियर सिटीज़न सपोर्ट बेंच' का गठन। इस विशेष इकाई में रिटायर्ड अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं। यहां आने वाली शिकायतें समाज की एक गंभीर तस्वीर सामने रखती हैं— बेटे–बहू द्वारा प्रताड़ना, संपत्ति के लिए दबाव, जबरन वृद्धाश्रम भेजना, शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट, भोजन से वंचित करना और घर से निकाल देना जैसी घटनाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब तक इस केंद्र में लगभग 200 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 130 मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है। यह आंकड़े न केवल इस पहल की सफलता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सही समय पर संवाद और संवेदनशील हस्तक्षेप कितने प्रभावी हो सकते हैं। दुर्ग का 'काउंसलिंग–फर्स्ट' मॉडल छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है, जिसने पारिवारिक विवाद समाधान को नई दिशा दी है। जहां कई राज्यों में अब भी पारंपरिक और एकतरफा दृष्टिकोण हावी है, वहीं दुर्ग ने महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों—सभी को एक मंच पर समान रूप से सुनने का संतुलित मॉडल विकसित किया है।

संवाद आधारित यह व्यवस्था न केवल विवादों को समय रहते सुलझा रही है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रही है। इसी कारण यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी उदाहरण बनकर उभर रही है, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने की दिशा में देख रहे हैं।

वैशाली नगर में 'लक्ष्मी' के आगमन पर विधायक का तोहफा

'माँ का दुलार' किट से सजेगा बेटियों का बचपन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई । वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने क्षेत्र की जनता को आज एक बड़ी और भावुक सौगात दी है। विधायक ने माँ का दुलार – माँ शिशु सुरक्षा कवच योजना का आगाज़ किया है। इस योजना के तहत 1 मई (मजदूर दिवस एवं बुद्ध पूर्णिमा) के बाद जन्म लेने वाली हर बेटी को विधायक की ओर से एक विशेष 'गिफ्ट ट्रॉली सूटकेस' भेंट किया जाएगा, जिसमें नवजात और माँ की जरूरत का हर सामान मौजूद होगा।

बेटी का चाचा बन कर निभाऊंगा फ र्ज: योजना की घोषणा करते हुए विधायक रिकेश सेन ने कहा कि मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ और मैंने देखा है कि कैसे संसाधनों के अभाव में

माताओं को पुराने गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था। मैं चाहता हूँ कि वैशाली नगर में जन्म लेने वाली हर बेटी को अमीरों जैसी सुख–सुविधा मिले। मैं उस बेटी का चाचा कहलाना पसंद करूँगा। विधायक द्वारा दी जाने वाली इस ट्रॉली में कुल 25 से अधिक ब्रांडेड सामग्रियां शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से बाहर से मंगवाया गया है और इस पूरे कीट की कीमत लगभग 11 हजार रूपये है।

शिशु के लिए: 11 पैडेड आधुनिक लंगोट (सोखने की क्षमता वाले), ब्रांडेड सॉफ्ट कंबल, स्वेटर, मोजे, कैप, तौलिया, बेबी किट (लोशन, साबुन, शैम्पू), मालिश तेल, दूध की बोतल, खिलौने और नामकरण के लिए विशेष ड्रेस। माता के लिए: पौष्टिक आहार हेतु खजूर और खुमानी (ड्राई फ्रूट्स), शॉल, बेडशीट, मोजे, सेनेटरी पैड और नहाने का साबुन। स्वच्छता का ध्यान : घर के उपयोग के लिए बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बेबी वाइप्स और वाटरप्रूफ मैट (चादर गीली होने से बचाने के लिए)। यह योजना पूर्णत: निशुल्क है और इसका उद्देश्य मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों की मदद करना है। विधायक ने स्पष्ट किया कि यह किट केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाला हर सामान उच्च गुणवत्ता का है। प्रारंभ तिथि: 1 मई 2026 से पात्रता: वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जन्म लेने वाली बेटियां। विशेषता* : माँ और बच्चे दोनों की सेहत और स्वच्छता का पूर्ण पैकेज।

वैशाली नगर के निवासियों ने विधायक की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यह न केवल एक आर्थिक मदद है, बल्कि बेटियों के प्रति समाज के नजरिए को बदलने की एक सकारात्मक कोशिश भी है।

रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग से श्रद्धालुओं का भव्य प्रस्थान

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज दुर्ग जिले से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों के श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। पूरे स्टेशन परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्टेशन पर श्रद्धालुओं का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उनकी सुखद व सुरक्षित यात्रा की कामना की। महापौर ने कहा कि यह योजना आमजन को भगवान श्रीराम के दर्शन का अवसर प्रदान कर रही है। यात्रा पर रवाना हो रहे श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज के हर वर्ग को अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन का लाभ मिल रहा है।

इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन,आयुक्त सुमित अग्रवाल, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, रेलवे विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नगर निगम दुर्ग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सामान्य सभा आयोजित

जनप्रतिनिधियों की सहमति से प्रस्ताव बहुमत से पारित, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : महापौर

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग में 131वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023) विषय पर विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया गया। यह सभा नगर निगम परिसर स्थित मोतीलाल वोरा सभागार में संपन्न हुई।सभा की अध्यक्षता निगम सभापति श्याम शर्मा द्वारा की गई।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 संशोधन विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार–विमर्श किया। चर्चा के दौरान महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विस्तृत चर्चा

के पश्चात नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 संशोधन विधेयक प्रस्ताव को विशेष सामान्य सभा में बहुमत से पारित किया गया। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने तथा समाज में उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इस प्रकार के निर्णयों से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उचित स्थान मिलेगा और समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम दुर्ग महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते रहेंगे। महापौर अलका बाघमार ने विशेष सभा में कहा कि 131वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को संसद में पारित नहीं किए जाने के विरोध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। यह अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका सशक्त और प्रभावी हो सके। महापौर ने जोर देते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समाज के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार एमआईसी सदस्य देवनारायण चन्द्राकर,नरेन्द्र बंजारे,शेखर चन्द्राकर,लीना दिनेश देवांगन,मनीष साहू,ज्ञानेश्वर ताम्रकार,निलेश अग्रवाल,शिव नायक,शशि साहू, लीलाधर पाल, हर्षिका सँभव जैन,आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले सहित जन प्रतिनिधि के अलावाअधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहे।

नगर पालिक निगम भिलाई में 'वूमेन फॉर ट्री' योजना की समीक्षा
12,500 पौधों के संरक्षण का जिम्मा संभाल रहीं हैं महिला समूह

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। केंद्र सरकार एवं शासन की महत्वाकांक्षी योजना 'वूमेन फॉर ट्री' के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। इस योजना के तहत निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 12,500 पौधों का रोपण किया गया है। इन पौधों के उचित रखरखाव, सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम मुख्यालय में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित करना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ महिलाओं को स्वरोजगार और प्रबंधन से

जोड़ा जा सके। रोपे गए 12,500 पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए नियमित खाद, पानी और सुरक्षा घेरे की व्यवस्था पर जोर दिया गया।

प्रत्येक क्षेत्र के समूहों को उनके द्वारा लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्य योजना की बारीकियों पर चर्चा की ।

अजीत कुमार तिग्गा मुख्य अभियंता ने पौधों की शत–प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। वेशराम सिन्हा अधीक्षण अभियंता ने आधारभूत संरचना और सिंचाई की व्यवस्थाओं पर मार्गदर्शन दिया। तिलेश्वर साहू उद्यान अधिकारी ने तकनीकी पहलुओं और पौधों की किस्मों के अनुसार देखभाल के तरीके बताए। श्वेता महेश्वर उप अभियंता ने क्षेत्रवार महिला समूहों के समन्वय और डेटा प्रबंधन की जानकारी साझा की। मुख्य अभियंता श्री तिग्गा ने बैठक में स्पष्ट किया कि यह योजना केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय कर इस अभियान को जन–आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

विश्व इस्पात दिवस पर 'हज़ान' राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बीएसपी की दोहरी जीत

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। विश्व इस्पात दिवस के अवसर पर सेल सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (एसएसओ), रांची द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'हज़ान' राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस प्रतियोगिता में देशभर से प्रतिभागियों ने भाग लेकर औद्योगिक सुरक्षा जागरूकता एवं परिचालन उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया।

भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रतिनिधित्व इस्पात गलन शाला–2 (एसएमएस2) की टीमों द्वारा किया गया। कार्यपालक श्रेणी में सहायक महाप्रबंधक अरिंदम कर, वरिष्ठ प्रबंधक के. पवन कुमार एवं सहायक प्रबंधक सुमित कुमार ने सुरक्षा मानकों की गहन समझ, तकनीकी दक्षता एवं प्रभावी प्रतिक्रिया कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान अर्जित किया। इसी प्रकार, गैर–कार्यपालक श्रेणी में विनय, शिव कुमार एवं चंदन वर्मा की टीम ने उत्कृष्ट समन्वय एवं परिचालन कौशल का परिचय देते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र को इस प्रतियोगिता में दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इस उपलब्धि पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा संयंत्र प्रबंधन एवं सहकर्मियों द्वारा उनकी सराहना की गई। 'हज़ान' प्रतियोगिता इस्पात उद्योग में सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने एवं आपात स्थितियों के प्रति तत्परता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास-खबर

डिजिटल लेबर चौक ई-श्रम साथी एप से श्रमिकों को मिलेगा सीधा रोजगार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने श्रमिकों और नियोजकों के बीच की दूरी कम करने तथा रोजगार के अवसरों को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए डिजिटल लेबर चौक ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह आधुनिक प्लेटफॉर्म राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को सीधे रोजगार से जोड़ने का कार्य करेगा। इस ऐप के माध्यम से अब नियोजक और श्रमिक सीधे एक-दूसरे से संपर्क कर सकेंगे, जिससे रोजगार प्रक्रिया अधिक सरल और तेज होगी। शासन की इस पहल से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और श्रमिकों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर त्वरित काम उपलब्ध कराया जाएगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि डिजिटल लेबर चौक ई-श्रम साथी एप के माध्यम से रोजगार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी। श्रमिक और ठेकेदार गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर आसानी से अपना पंजीयन स्वयं कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सुलभ बनेगी। इस प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों को उनके हुनर और अनुभव के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें उचित अवसर मिलने के साथ-साथ आय में भी वृद्धि होगी। शासन का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाना है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा जिला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर श्रमिकों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।

ज्ञान भारतम अभियानः देवरी एवं खैरवार में प्राप्त हुई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की समृद्ध ज्ञान-विज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से ज्ञान भारतम् एप के माध्यम से पांडुलिपियों के सर्वेक्षण का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुंगेली जिले में भी गांव-गांव स्तर पर प्राचीन पांडुलिपियों की खोज और संरक्षण का कार्य तेज गति से जारी है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार तथा डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी मायानंद चन्द्रा के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर्स लेखराम राहू एवं तीरथप्रसाद बड़गईयाँ द्वारा जिले के विभिन्न गांवों में पांडुलिपि सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान ग्राम देवरी में गोपचन्द्र शेण्ड्रे के पास उनके पिता स्वर्गीय भगऊ शेण्ड्रे द्वारा हस्तलिखित दो महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक पांडुलिपि लगभग 376 पृष्ठों की है, जबकि दूसरी में 62 पृष्ठ हैं। इन ग्रंथों में बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र, उनके आदर्शों, जीव की उत्पत्ति, सृष्टि एवं आयुर्वेद जैसे विषयों का उल्लेख पाया गया है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। इसी प्रकार विकासखंड लोरमी के ग्राम खैरवार में द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी के यहां भी लगभग 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ये पांडुलिपियां देवनागरी लिपि में हैं, जिनकी भाषा संस्कृत और हिंदी का मिश्रण प्रतीत होती है।

बस्तर के छोटे किलेपाल में दिव्यांगों के जीवन में लौटा आत्मसम्मान

रायपुर। राज्य शासन द्वारा बीते वर्ष आयोजित सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जहाँ प्रशासन की तत्परता दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों के जीवन में स्वावलंबन का नया अध्याय लिख रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के सुदूर जनपद पंचायत बास्तानार अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटे किलेपाल से एक हृदयस्पर्शी सफलता की कहानी सामने आई है, जिसने शासन की संवेदनशीलता और जनहितैषी दृष्टिकोण को सिद्ध किया है। दंतेवाड़ा जिले की सीमा से लगे इस सुदूर ग्राम छोटे किलेपाल के निवासी श्री सामनाथ ठाकुर और रीता ठाकुर, जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, दिव्यांग होने के कारण लंबे समय से गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। शारीरिक अक्षमता के चलते उन्हें अपनी हर छोटी-बड़ी आवश्यकता और दैनिक वस्तुओं के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर पूरी तरह आश्रित होना पड़ता था। इस निर्भरता के कारण न केवल उनका आत्मसम्मान प्रभावित हो रहा था, बल्कि आर्थिक तंगी के दौर में वे परिवार पर भी एक अतिरिक्त बोझ महसूस कर रहे थे। मान चुके इन ग्रामीणों के लिए पिछले वर्ष आयोजित सुशासन तिहार आशा की एक नई किरण बनकर आया।

हर हाथ को काम, हर श्रमिक को सम्मानः विष्णु देव सरकार की प्रतिबद्धता

श्रीकंचनपथ न्यूज

छगन लोन्हारे
उप संचालक जंनसंपर्क

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते 02 साल 04 माह में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 800 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में श्रमिकों के 200 बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा।

मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री श्री साय का मानना है कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण भी तकनीक के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है।

प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश में विष्णु देव सरकार के सुशासन में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर हाथ को काम इस दिशा में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 256 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि विष्णु देव के सरकार की सोच है कि हर हाथ को काम मिले उसका उन्हें उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है। इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 38 भोजन केन्द्र संचालित है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 5 रूपये में गरम भोजन, दाल चावल, सब्जी, आचार प्रदाय किया जा रहा है, जिसका विस्तार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। श्रमिक आवास की राशि प्रति आवास 01 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी है। इसी तरह ई-रिक्शा की राशि भी एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपए की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 5 सितंबर 2008 से अब तक 33 लाख 14 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मंडल द्वारा 26 योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। एक प्रतिशत उपकर (सेस) से वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि मंडल गठन से अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपये का उपकर संग्रहित हुआ है। मार्च 2026 तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में व्यय किए जा चुके हैं।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का मुख्य दायित्व श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए 76 करोड़ 38 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

पशु सखियों के प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पशुपालन आधारित आजीविका को सशक्त करने की दिशा में एक प्रभावी पहल सामने आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेशभर में पशु सखी मॉडल के जरिए महिलाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है, जिससे वे अपने साथ-साथ अन्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी क्रम में बलरामपुर जिले में 30 पशु सखियों के लिए 17 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में संचालित हो रहा है, जहां उन्हें पशुपालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और व्यावहारिक पहलुओं की गहन जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पशुओं की समुचित देखभाल, संतुलित आहार प्रबंधन, नियमित टीकाकरण, नस्ल सुधार, रोगों की पहचान एवं प्राथमिक उपचार जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही पशु चिकित्सालय एवं गौशालाओं के भ्रमण के माध्यम से पशु सखियों को जमीनी स्तर पर पशुधन प्रबंधन की व्यवहारिक समझ विकसित कराई जा रही है। जिला पंचायत बलरामपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पशु सखी जैसी पहलें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को समय पर मार्गदर्शन और सेवाएं मिलेंगी, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी।

प्रदेश में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, पशुधन स्वास्थ्य सुधार और सतत ग्रामीण विकास को भी गति दे रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त पशु सखियां अपने-अपने गांवों में पशुपालन सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरेंगी और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण में अहम योगदान देंगी।

खेल अकादमी में चयन के लिए 204 खिलाड़ियों के खेल कौशल का किया गया परीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए आज रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में तीरंदाजी, फुटबॉल और वेटलिफ्टिंग के 204 खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया गया। आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों का चयन मोटर एबिलिटी एवं खेल कौशल के आधार पर किया जाता है। चयन ट्रायल के तीसरे दिन 30 अप्रैल को हॉकी और एथलेटिक्स अकादमी में चयन के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल और दक्षता परीक्षण किया जाएगा। अगले दिन 1 मई को मापदंडों पर खरे उतरने वाले खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आवास, भोजन व मेडिकल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में ज्ञानेश्वरी यादव को गोल्ड मेडल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट आईबीएफसी यूनिवर्सल कप-2026 में ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। समोआ के एपिया स्थित तुआनाईमाटो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 अप्रैल से 2 मई तक अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।

प्रतियोगिता में 70 देशों के लगभग 500 खिलाड़ी एवं 200 अधिकारी शामिल हो रहे है। ज्ञानेश्वरी ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपने ग्रुप में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के लिए क्वालीफिकेशन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वरी इससे पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और सीनियर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुकी है।

गौरवशाली और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली उपलब्धियों के लिए राज्य शासन द्वारा उन्हें गुण्डाधुर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानेश्वरी अभी छत्तीसगढ़ पुलिस में राजनांदगांव में कार्यरत है। अपने कोच अजय लोहार विश्वकर्मा के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से ज्ञानेश्वरी इस मुकाम तक पहुंची है।

खनन क्षेत्रों में ड्रोन की निगरानी से खनिज संसाधन की सुरक्षा में मिल रही मदद

हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा, नाइट विजन और एआई प्रणाली से लैस ड्रोन से होती है व्यापक और सटीक निगरानी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगाम कसने के लिए तकनीक और नवाचार का सहारा लेते हुए एक बड़ी और निर्णायक पहल की है। इसी कड़ी में अब खनन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की शुरुआत कर दी गई है, जो राज्य में कानून व्यवस्था, खनिज संसाधन की सुरक्षा तथा राजस्व संरक्षण की दिशा में अहम कदम साबित हो रहा है।

राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को जड़ से खत्म किया जाए। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से अब खनन क्षेत्रों में रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी, जिससे अवैध उत्खनन, परिवहन और संबंधित गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। यह कदम न केवल राजस्व हानि को रोकेगा, बल्कि अवैध कारोबार में लिप्त तत्वों के लिए कड़ा संदेश भी साबित होगा। खनिज विभाग का मैदानी अमला पहले से ही अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब ड्रोन तकनीक के जुड़ने से इस कार्रवाई की गति और सटीकता दोनों बढ़ेंगी। ड्रोन से लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज और 120 मीटर तक ऊंचाई से निगरानी की क्षमता के चलते बड़े और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान कर मौके पर कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे अवैध गतिविधियों में संलिप्तों के बच निकलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन में उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरा, नाइट विजन और एआई आधारित विश्लेषण प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जो व्यापक और सटीक निगरानी सुनिश्चित करती हैं। इसके जरिए बड़े और दुर्गम खनन क्षेत्रों पर भी आसानी से नजर रखी जा सकती है।

यह पहल स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। सरकार का यह साहसिक निर्णय न केवल कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि खनिज संसाधनों के संरक्षण और पारदर्शी राजस्व व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। ड्रोन निगरानी की यह नई व्यवस्था राज्य में सुशासन और तकनीकी नवाचार का मजबूत उदाहरण बनकर उभर रही है।

इसी कड़ी में 29 अप्रैल 2026 को जिला कांकेर के तहकापार रेत खदान क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए सघन निगरानी और छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों एवं उपकरणों की पहचान की गई। ड्रोन निगरानी शुरू होते ही अवैध गतिविधियों में शामिल लोग अपने वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए।

जनजातीय उत्थान पर बड़ा फोकसः नक्सल मुक्त क्षेत्रों में तेज़ होगा विकास, 'नियद नेल्ला नार 2.0' जल्द

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास को लेकर व्यापक चर्चा की गई और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर, जो भौगोलिक रूप से केरल से भी बड़ा क्षेत्र है, दशकों तक विकास से वंचित रहा, लेकिन अब वहां योजनाओं का तीव्र विस्तार हो रहा है और विकास की नई धारा स्थापित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देवगुड़ी और सरना स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी और कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से प्रदेश के 6600 गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ की जा रही हैं, जबकि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 32 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। बैठक में नियद नेल्ला नार योजना की उल्लेखनीय सफलता पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने इसके अगले चरण के रूप में नियद नेल्ला नार 2.0 को शीघ्र लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस उन्नत पहल के माध्यम से सुदूर अंचलों में बिजली, पानी, सड़क और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के तहत 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच का कार्य निरंतर प्रगति पर है। मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय भूमि के दीर्घकालीन लीज पर दोहन के मामलों की जांच के निर्देश दिए। साथ ही कोरवा और संसारी उरांव जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को शीघ्र केंद्र सरकार को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साय ने छात्रावासों की सीट वृद्धि, उनके बेहतर रखरखाव तथा शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने नक्सल मुक्त क्षेत्रों में बच्चों के लिए त्वरित शिक्षण व्यवस्था विकसित करने और खुले में कक्षाएं संचालित न करने के स्पष्ट निर्देश दिए। अम्बिकापुर नेशनल हाईवे के निर्माण में हो रही धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही बरसात के दौरान कटने वाले मार्गों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री एवं परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम ने कहा कि बस्तर, सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय अंचलों में लंबे समय तक नक्सलवाद विकास की सबसे बड़ी बाधा बना रहा। बीते चार दशकों की इस चुनौती से मुक्ति मिलने के बाद अब इन क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं तेज क्रियान्वयन संभव हो सका है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनजातीय समुदाय तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है और उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

श्री नेताम ने यह भी बताया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवेदनशील मुद्दों का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बसाहटों तक अब बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। साथ ही नए छात्रावासों के निर्माण से दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल रहा है, जिससे उनके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वनमंत्री केदार कश्यप, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव मरपच्ची, विधायक रायमुनी भगत, विधायक चैतराम अटामी, विधायक विक्रम उसेंडी, विधायक उद्देश्वरी पैकरा, विधायक नीलकंठ टेकाम, विधायक आशाराम नेताम, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

किस एक्टर के साथ रिश्ते में हैं पूजा हेगड़े?

तारा सुतारिया के साथ जुड़ चुका है रूमर्ड बॉयफ्रेंड का नाम.....

खबरें हैं कि एक्ट्रेस पूजा हेगड़े एक एक्टर के साथ रिश्ते में हैं। आइए जानते हैं दोनों पहली बार कहां मिले थे और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड का पहले किस अभिनेत्री से नाम जुड़ चुका है? बी टाउन में डेटिंग की नई अफवाहों का बाजार गर्म है। खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस पूजा हेगड़े एक्टर रोहन मेहरा के साथ रिलेशनशिप में हैं। उनके कथित रोमांस को लेकर चल रही अटकलों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा है। इस खबर ने फैंस और फॉलोअर्स, दोनों का ही ध्यान खींचा है। पूजा हेगड़े वरुण धवन के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर भी चर्चा में हैं।

पहली बार कहां मिला था जोड़ा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जोड़ा पिछले कुछ वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहा है। उन्होंने अपने रिश्ते को काफी हद तक प्राइवेट रखा है। हेगड़े और मेहरा के बीच कनेक्शन की पहली अफवाहें 2020 में तब सामने आई थीं, जब उन्हें हर्ष वर्धन कपूर की एक पार्टी में एक साथ देखा गया। उस समय, इन अटकलों को खारिज कर दिया गया था।

माना जा रहा था कि हेगड़े किसी क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन वर्षों में उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ है।

कौन हैं रोहन मेहरा?

रोहन मेहरा, जिनका जन्म 1991 में केन्या में हुआ था, दिवंगत बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा के बेटे हैं। अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, रोहन ने 2018 में फिल्म 'बाजार' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। फिलहाल, वे नेटफ्लिक्स के आने वाले प्रोजेक्ट 'फैमिली बिजनेस' में नजर आने वाले हैं।

इस अभिनेत्री से भी जुड़ चुका नाम

मेहरा के इंस्टाग्राम पर 110,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने बायो में खुद को एक फिल्ममेकर बताया है। हेगड़े के साथ अपने कथित रिलेशनशिप से पहले, उनका नाम एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ भी जुड़ा था। अब उनकी रोमांटिक हिस्ट्री में एक और दिलचस्प पहलू जुड़ गया है। अब फैंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दोनों का रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ता है।

हुमा कुरैशी का अप्रैल महीना कैसा बीता एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया शेयर

अप्रैल महीना समाप्त होने वाला है। ऐसे में अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीते महीने की एक झलक पेश की है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अप्रैल के महीने के बचे हुए सामान को साझा करते हुए स्वीकार किया कि उन्हें लगता है कि अप्रैल का महीना बहुत जल्दी बीत गया।

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, यह महीना बहुत तेजी से बीत रहा हैज अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ है।

एल्बम की पहली तस्वीर में हुमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर की अभिनेत्री की एक और शानदार तस्वीर थी, जिसमें वह मिरर सेल्फी में बेहद आकर्षक लग रही थीं।

कैफे में आराम करने से लेकर सड़क पर खुशी-खुशी अपनी कॉफी का आनंद लेने तक और खरीदारी करने तक, अप्रैल का महीना हुमा के लिए गतिविधियों से भरा हुआ था।

इस पोस्ट में हुमा द्वारा पसंद किए गए सभी स्वादिष्ट व्यंजनों की झलक भी मिलती है, जिनमें एक संतुलित देसी थाली, वड़ा पाव और बर्गर शामिल हैं।

काम की बात करें तो हुमा कुरैशी यश अभिनीत फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की रिलीज के लिए तैयार हो रही हैं, जिसमें वह एलिजाबेथ की भूमिका निभाएंगी।

इससे पहले फिल्म निर्माता गीतु मोहनदास ने खुलासा किया था कि एलिजाबेथ की भूमिका निभाने के लिए एक उच्च क्षमता और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस वाले अभिनेता की आवश्यकता थी, जो गुण उन्हें हुमा में मिले।

मोहनदास ने सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट करते हुए कहा, इस भूमिका के लिए कास्टिंग शायद सबसे मुश्किल काम था। इस किरदार के लिए एक ऐसे कलाकार की जरूरत थी, जिसमें जबरदस्त प्रतिभा और दमदार व्यक्तित्व हो। जिस पल हुमा मेरे सामने आई, मैंने महसूस किया कि उनमें कुछ दुर्लभ गुण मौजूद हैं।

निर्देशक ने आगे कहा कि हुमा में एक सहज परिष्कार और तीव्रता थी, जिसने एलिजाबेथ के चरित्र को तुरंत जीवंत कर दिया।

मोहनदास ने आगे कहा, हुमा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो किसी भूमिका की कलात्मक व्याख्या पर सवाल उठाती हैं, उसकी पड़ताल करती हैं और उसे चुनौती देती हैं, और यह संवाद हमारी रचनात्मक यात्रा का एक अभिन्न अंग बन गया। उन्हें हमेशा से प्रतिभा का धनी माना जाता रहा है, लेकिन यह प्रदर्शन सिनेमा पर एक निर्विवाद, प्रभावशाली नई उपस्थिति के आगमन का निर्णायक मोड़ साबित होगा।

कामकाजी महिलाएं गर्मियों के दौरान इन 5 ब्यूटी टिप्स को अपनाएं, लगेंगी खूबसूरत

गर्मियों में कामकाजी महिलाओं के लिए मेकअप और त्वचा की देखभाल को संभालना मुश्किल हो सकता है। इस मौसम में पसीना और उमस त्वचा को चिपचिपा बना देती है, जिससे मेकअप भी खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार ब्यूटी टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में भी ताजगी और खूबसूरती के साथ ऑफिस जा सकती हैं और खुद को तरोताजा महसूस कर सकती हैं।

नियमित रूप से त्वचा को साफ करें

गर्मियों में त्वचा पर मृत कोशिकाएं और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे त्वचा बेजान और थकी-थकी सी लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से त्वचा की सफाई करना जरूरी है। हफ्ते में 2-3 बार हल्के हाथों से स्क्रब करें, ताकि मृत त्वचा हट जाए और त्वचा को नई ऊर्जा मिले। इससे आपकी त्वचा साफ और ताजगी भरी महसूस होगी और मेकअप भी लंबे समय तक टिकेगा।

हल्की क्रीम लगाएं

गर्मियों में भारी क्रीम का इस्तेमाल करने से त्वचा चिपचिपी लग सकती है, जिससे बचने के लिए हल्की जेल आधारित क्रीम लगाएं। यह त्वचा को नमी प्रदान करेगी और चिपचिपाहट भी नहीं होगी। जेल आधारित क्रीम जल्दी अवशोषित हो जाती है और त्वचा को ताजगी भरी महसूस कराती है। इसके अलावा यह पसीने को भी कम करती है और त्वचा को ठंडक देती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगी।

धूप से बचाव वाली क्रीम इस्तेमाल करें

चाहे बादल हों या धूप, रोजाना धूप से बचाव की क्रीम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाती है। इसे लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और फिर अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह लगाएं। इसे हर 2-3 घंटे के बाद दोबारा लगाएं, खासकर अगर आप बाहर हैं तो। इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी और झुलसने का खतरा कम होगा।

हल्के रंगों की लिपस्टिक का चयन करें

गर्मियों में भारी और गहरे रंग की लिपस्टिक लगाने से होंठ चिपचिपे लग सकते हैं। इसलिए, गुलाबी, पीच या न्यूड जैसे हल्के रंग चुनें। ये रंग न केवल आपको ताजगी भरी लुक देंगे, बल्कि पूरे दिन आरामदायक भी महसूस होगा। इसके अलावा हल्के रंग की लिपस्टिक आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक भी लाएगी और आपको हर समय खूबसूरत महसूस करवाएगी। इस तरह आप गर्मियों में भी स्टाइलिश और आरामदायक दिख सकती हैं।

बालों का साधारण स्टाइल अपनाएं

गर्मियों में बालों को संभालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्हें साधारण रखें। पोनीटेल, जूड़ा या फिर चोटी जैसे हेयरस्टाइल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

ये न केवल स्टाइलिश दिखते हैं, बल्कि पसीने से भी बालों की सुरक्षा करते हैं और उन्हें उलझने से बचाते हैं। इन ब्यूटी टिप्स को अपनाकर आप गर्मियों में भी ताजगी और खूबसूरती के साथ ऑफिस जा सकती हैं और खुद को तरोताजा महसूस कर सकती हैं।

रिलीज हुआ पैट्रियट का ट्रेलर, ममूटी और मोहनलाल को देखकर खुश हुए फैंस

मोहनलाल और नयनतारा जैसे बड़े सितारों से सजी अपकमिंग फिल्म पैट्रियट के ट्रेलर का दर्शकों को काफी इंतजार था। उनका इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें ममूटी और मोहनलाल बेहतरीन किरदार में नजर आए हैं।

तीन मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सरकार एक ऐसा ऐप बनाती है, जिससे आम जनता की निजी जानकारियां सरकार तक पहुंचती हैं। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बीच डॉक्टर डैनियल (ममूटी) के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह किसी साजिश का शिकार हुए हैं। इसके बाद ट्रेलर में मोहनलाल नजर आते हैं। चूंकि ममूटी और मोहनलाल बचपन में दोस्त थे इसलिए वह ममूटी की बिना पूछे मदद करना चाहते हैं। हालांकि दोनों के बीच टकराव हो जाता है। फिल्म में हीरो कौन होगा और कौन विलेन होगा, यह फिल्म देखने पर पता चलेगा। ट्रेलर में ममूटी और मोहनलाल एक्शन अवतार में नजर आए हैं। इसमें नयनतारा की भी झलक दिखी है, जो अहम किरदार में हैं। ट्रेलर में फहद फाजिल भी अहम किरदार में नजर आए हैं।

पैट्रियट का हिंदी ट्रेलर देखकर कई यूजर्स ने इस पर कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा है ममूटी, मोहनलाल और नयतारा। एक ही फिल्म में तीन पावर हाउस। एक दूसरे यूजर ने लिखा है ममूटी पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2026, मोहनलाल दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता 2025। एक और यूजर ने लिखा एक ही फ्रेम में सभी मलयालम लीजेंड।

पैट्रियट का निर्देशन महेश नारायणन ने किया है। इसमें ममूटी, मोहनलाल, नयनतारा, फहद फाजिल, दर्शना राजेंद्रन, कुंचको बोबन और रेवती भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले इसे 23 अप्रैल, 2026 को रिलीज करने का प्लान था।

कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी का ट्रेलर रिलीज

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म दादी की शादी का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा भी अहम किरदार में नजर आए हैं। निर्देशन आशीष आर. मोहन ने किया है, जो पहले खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म का निर्माण आर-टेक स्टूडियोज, बीइंग-यू स्टूडियोज, शिमला टॉकीज के बैनर तले किया गया है।

ट्रेलर दिग्गज अभिनेत्री के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक दादी उम्र की सीमाओं को तोड़ते हुए दोबारा शादी करने का फैसला लेती है, क्योंकि उसे विधवा होकर नहीं, बल्कि सुहागन बनकर दुनिया से जाना है। इस फैसले का परिवार पर क्या-क्या असर पड़ता है, यही फिल्म दिखाती है। नीतू और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बेहद ग्लैमरस हैं सनी देओल की ऑन-स्क्रीन बहू, बिकनी में सिमरत कौर ढाती हैं कहर

सिमरत कौर ने फिल्म गदर 2 से खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म में उन्होंने सनी देओल की बहू का रोल प्ले किया था। फिल्म में सिमरत ने सादगी भरें अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया था। वहीं रियल लाइफमें वो बेहद ही ग्लैमरस हैं। हाल ही में उन्होंने बिकनी में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं।

सिमरत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी ये फोटोज शेयर कर सभी का ध्यान खींच लिया है। सिमरत ने मल्टीकलर प्रिंटेड बिकिनी टॉप और स्कर्ट पहना है। जिसमें वो काफी स्टाइलिश दिख रही हैं। फोटोज में सिमरत बीच पर कॉन्फिडेंट अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने कई पोज दिए हैं। एक फोटो में एक्ट्रेस सन किस्ड लेती नजर आ रही हैं। उनके चेहर पर ग्लो भी साफ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी में वो कॉन्फिडेंट अंदाज में सेल्फी लेती दिखीं। नो मेकअप लुक में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं। उनकी इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। फैंस इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें, सिमरत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

खास खबर

भारतीय वुडबॉल टीम में आकाश दुबे ने बनाई जगह, हांगकांग में लहराएंगे तिरंगा

रायपुर। सरगुजा वुडबॉल संघ के आकाश दुबे का चयन भारतीय वुडबाल टीम में हुआ है। वे हांगकांग इंटरनेशनल वुडबॉल चैंपियनशिप-2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगामी 30 अप्रैल से 4 मई तक यह इंटरनेशनल चैंपियनशिप आयोजित है। भोपाल में आयोजित ओपन इंटरनेशनल चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के दम पर आकाश का चयन भारतीय टीम में हुआ है। इंडिया कैंप में उनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल हासिल किया है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चौंपियनशिप में उत्कृष्ट खेल दिखाया था। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने आकाश की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि सरगुजा क्षेत्र से भारतीय टीम में चयन होना बहुत गर्व की बात है। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने यह स्थान हासिल किया है।

सीजीपीएससी एवं व्यापम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज न्यास के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारियों के लिए नवप्रेरणा नि:शुल्क कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इसमें नवीन बैच की कक्षाएं मई माह की प्रथम सप्ताह से प्रारंभ की जाएगी एवं इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 30 अप्रैल से 6 मई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंगाए गये है। नि:शुल्क कोचिंग में अध्ययन के लिए नयूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। एवं शिक्षक भर्ती हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कोचिंग में अध्ययन का लाभ ले सकते है। कोचिंग के लिए 60 सीट निर्धारित है विद्यार्थियों का चयन पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर होगा।

पोट्ठ लईका पहल से कुपोषण में आयी कमी

राजनांदगांव। जिला प्रशासन द्वारा जिले में कुपोषण मुक्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा एनआरएलएम के माध्यम से पोट्ठ लईका पहल अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जून 2025 से प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक गुरूवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पालक चौपाल का आयोजन कर पालकों को तिरंगा भोजन के महत्व, पौष्टिक आहार, स्तनपान, एनीमिया, रोकथाम सहित जरूरी विषयों पर जानकारी दी जाती है तथा जरूरत होने पर आवश्यक दवाईयां उपलग्ध कराई जाती है। माह जून 2025 की स्थिति में अभियान अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के कुल 55797 बच्चों को लक्षित किया गया। जिसमें जून 2025 में गंभीर कुपोषित 731, मध्यम कुपोषित 6181, अति गंभीर कुपोषित 443, मध्यम कुपोषित 2396 बच्चे थे। कुल 9751 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने हेतु लक्ष्य रखते हुए जून 2025 से पूरे जिले में पोट्ठ लईका पहल अभियान प्रारंभ किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के उन्नत संस्करण 'सेवा सेतु' का शुभारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा आमजन तक प्रभावशाली, पारदर्शी और डिजिटल नागरिक सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के उन्नत संस्करण 'सेवा सेतु' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डिजिटल नागरिक सेवाएं और अधिक सशक्त और प्रभावी होंगी। वर्ष 2003 में प्रारंभ हुए चॉइस मॉडल से लेकर वर्ष 2015 के ई-डिस्ट्रिक्ट और अब 'सेवा सेतु' तक छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में एक लंबी और उल्लेखनीय यात्रा तय की है तथा यह प्लेटफॉर्म अब नागरिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बन चुका है, जिससे लाखों नागरिकों को लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'सेवा सेतु' के माध्यम से अब एक ही पोर्टल पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाओं की जानकारी सहज रूप से प्राप्त की जा सकेगी। आय, जाति, निवास, राशन कार्ड और विवाह पंजीयन जैसे प्रमुख प्रमाण-पत्रों सहित अब तक 3.2 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं और इतने ही प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 30 से अधिक विभागों के एकीकरण के साथ यह प्लेटफॉर्म एक सशक्त वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'सेवा सेतु' राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई मजबूती प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का संचालन राज्य स्तर पर चिप्स (ष्ट।द्बक्क्र) द्वारा किया जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (छ्वद्गत्र्स) के माध्यम से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। नई प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ख्द्ब), आधार, व्हाट्सएप और 'भाषिणी' जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकृत उपयोग किया गया है, जिससे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, सेवा की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजी लॉकर, ई-प्रमाण और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण कर सेवाओं को और अधिक सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाया गया है। 'सेवा सेतु' में ट्रेजरी और ई-चालान का एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे तथा डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से संभव होगी। पोर्टल में क्यूआर कोड आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल सिग्नेचर, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं तथा यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे भाषा की बाधा समाप्त हो गई है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवाओं की समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेशन, समय-सीमा संकेतक और स्वत: शिकायत पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी। राज्य में सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से अधिक चॉइस सेंटर और 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय हैं, जहां से नागरिक आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

'सेवा सेतु' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनसेवा के केंद्र में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से बाधारहित बनाया गया है, जिससे शासन और नागरिकों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है और सेवाएं सीधे नागरिकों के हाथों तक पहुंच रही हैं।व्हाट्सएप इंटरफेस के माध्यम से नागरिक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे, पावती रसीद और दस्तावेजों के लिंक तुरंत प्राप्त कर सकेंगे तथा अनुमोदन के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे।

वर्तमान में यह सुविधा 25 सेवाओं के लिए उपलब्ध है, जिसे शीघ्र ही सभी सेवाओं तक विस्तारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रमाण-पत्र में क्यूआर कोड आधारित सत्यापन की सुविधा दी गई है, जबकि कैप्चा, ओटीपी और ईमेल आधारित प्रमाणीकरण जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा को सुदृढ़ करती हैं।

जनगणना 2027: छत्तीसगढ़ में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य हेतु व्यापक तैयारियां, वीसी के माध्यम से समीक्षा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राष्ट्रीय महत्व का व्यापक अभियान जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य 01 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस संबंध में तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों एवं प्रमुख जनगणना अधिकारियों के साथ की गई।

बैठक में गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का व्यापक अभियान है, जिसके माध्यम से देश की जनसंख्या, आवासीय स्थिति एवं सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का सटीक आकलन किया जाता है, तथा मकान सूचीकरण एवं गणना इसकी आधारशिला है। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने निर्देशित किया कि सभी जिलों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। फील्ड कार्य के दौरान डेटा संग्रहण की विधि, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा संभावित चुनौतियों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी क्षेत्र गणना कार्य से न छूटे और न ही किसी क्षेत्र का दोहराव हो। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी किए जाएं, ताकि आम नागरिकों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों एवं उनसे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बड़ी आवासीय कॉलोनियों एवं अपार्टमेंट्स में जनगणना कार्य के सुचारू संचालन हेतु आवासीय कल्याण समितियों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर भी बल दिया गया।

कार्य की नियमित निगरानी हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या बाधा उत्पन्न होने पर उसका त्वरित समाधान किया जाए।

डिजिटल डेटा संग्रहण एवं गुणवत्ता पर जोर

जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने कहा कि इस बार जनगणना के आंकड़े मोबाइल एप के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं, अत: प्रत्येक प्रविष्टि को अत्यंत सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाए। किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही भविष्य की नीतियों एवं योजनाओं को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस कार्य में उच्च स्तर की जिम्मेदारी एवं सतर्कता आवश्यक है।

जनजागरूकता एवं फेक न्यूज पर नियंत्रण

जनजागरूकता के महत्व पर बल देते जीहुए जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने निर्देशित किया कि स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया एवं जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से आम नागरिकों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वे स्वेच्छा से सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। साथ ही सोशल मीडिया की सतत निगरानी कर किसी भी प्रकार की जाभ्रामक सूचना या फेक न्यूज का तत्काल खंडन किया जाए। नागरिकों की सुविधा के लिए टोलफ्री नंबर 1855 पर संपर्क की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने स्वयं की अपने परिवार की जनगणना

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने जनगणना 2026 के महाअभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल पोर्टल का उपयोग करते हुए अपने परिवार की स्व-गणना का कार्य स्वयं पूर्ण किया।

श्री कश्यप ने अपने निवास पर तकनीक के माध्यम से परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज कर यह संदेश दिया कि आधुनिक भारत में नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुलभता और शुचिता के साथ कर सकते हैं। स्व-गणना की इस प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात सांसद ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सटीक आंकड़े ही भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास का आधार बनते हैं। उन्होंने बताया कि स्व-गणना न केवल समय की बचत करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आपके परिवार की जानकारी बिना किसी त्रुटि के सीधे प्रशासन तक पहुँचे।

सांसद ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रगणकों की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं आगे आएं और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें। सांसद ने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी तकनीकी दक्षता का लाभ उठाते हुए अपने मोहल्ले और गांव के कम पढ़े-लिखे लोगों की स्व-गणना करने में सहायता करें।

वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ की तैयारियों की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सराहना

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जीरामजी) अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के प्रावधानों को ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए सुविचारित, व्यापक एवं रणनीतिक पहल की जा रही है, जो ग्रामीण विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने विशेष रूप से ग्राम चौपालों, ग्राम सभाओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे व्यापक जन-जागरूकता अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में त्तक्र कोड स्थापना की पहल को नवाचारपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे योजनाओं की जानकारी आमजन तक सरलता से पहुंचेगी तथा पारदर्शिता एवं मॉनिटरिंग को मजबूती मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के श्रम बजट को राज्य में मानव-दिवस सृजन रुझान को देखते हुए 850 लाख मानव-दिवस से बढ़ाकर 1250 लाख मानव-दिवस स्वीकृत किया गया है। उन्होंने इसे राज्य के सतत प्रयासों एवं बढ़ती कार्यगत आवश्यकता का सकारात्मक परिणाम बताया।

साय सरकार की पहल से महिलाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी दिशा में शुरू की गई 'महतारी वंदन योजना' आज हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रही है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि उन्हें परिवार और समाज में मजबूत भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान कर रही है।

साय सरकार द्वारा लागू की गई महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में प्रदाय की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार लाना, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और परिवार में निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना है। यह राशि महिलाओं के लिए छोटे-छोटे आर्थिक अवसरों का आधार बन रही है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।

कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली हेमा सिंह ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को केवल खर्च करने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में अपनाया। उन्होंने हर महीने मिलने वाले 1000 रुपये को बचाना शुरू किया और कुछ ही समय में अपने घर के पास एक छोटा सा किराना स्टोर खोल लिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि कहावत को चरितार्थ करते हुए शुरुआत की थी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने धीरे-धीरे इस छोटे व्यवसाय को सफल बना दिया। आज उनकी दुकान गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है और उनके परिवार की आय का मजबूत आधार बन चुकी है। हेमा सिंह की आय में स्थिरता आने से उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। अब वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही हैं और भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं। जहां पहले रोजमर्रा के खर्चों को लेकर चिंता बनी रहती थी, वहीं अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ झलकता है। हेमा सिंह अपनी सफलता का श्रेय महतारी वंदन योजना को देते हुए कहती हैं कि यह योजना उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

तकनीक आधारित 'प्रचार ऐप' से होगी आउटडोर मीडिया मॉनिटरिंग

अब हर होर्डिंग पर रहेगी रीयल-टाइम नजर, प्रिंटिंग पॉलिसी पर किया जा रहा है अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और नई पहलों के प्रचार-प्रसार में आउटडोर मीडिया एक अत्यंत प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित है। इसमें होर्डिंग्स, यूनिपोल्स, ब्रांडिंग, डिजिटल वॉल पेंटिंग्स और एलईडी वैन अभियान शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, बस स्टॉप्स तथा प्रमुख यातायात मार्गों जैसे उच्च आवागमन वाले स्थानों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से अधिक होता है।

आउटडोर मीडिया के क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग एक बड़ी चुनौती रही है। कई मामलों में यह शिकायतें सामने आई हैं कि वेंडर्स द्वारा सरकारी विज्ञापनों की स्थापना में देरी की गई या निगरानी के अभाव में उन्हें समय से पहले हटाकर उनकी जगह व्यावसायिक विज्ञापन लगा दिए गए।

इस समस्या के समाधान के लिए

जनसंपर्क विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम प्रचार ऐप विकसित किया गया है। यह प्रणाली तीन चरणों में कार्य करती है। पहले चरण में विभाग प्रचार अभियान की योजना बनाती है, पैनल में शामिल एजेंसियों और उनके एसेट्स का चयन कर प्रचार अभियान कार्य आवंटित करती है। दूसरे चरण में वेंडर्स प्रचार अभियान की समीक्षा कर क्रियान्वयन की योजना बनाती है और एसेट्स को माउंटर्स को सौंपती है। तीसरे चरण में माउंटर्स मैदानी स्तर पर निर्धारित स्थानों पर क्रिएटिव सामग्री स्थापित करती है।

रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए माउंटर्स हेतु एक एंड्रॉइड ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से माउंटर्स को जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो तीन चरणों में अपलोड करना अनिवार्य किया गया है-स्थापना से पहले, स्थापना के तुरंत बाद, और अभियान अवधि के दौरान प्रतिदिन कम से कम एक बार। इन तस्वीरों की पहले वेंडर एजेंसी द्वारा समीक्षा की जाती है और फिर उन्हें ऑनलाइन विभाग को भेजा जाता है।

यह एंड-टू-एंड प्रणाली पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है और विभाग को सभी सक्रिय अभियानों की लगभग वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराती है। इससे प्रत्येक आउटडोर एसेट की अलग-अलग ट्रैकिंग संभव हो पाती है और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसी क्रम में जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को पैनल में शामिल सभी एजेंसियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने आउटडोर मीडिया की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तकनीक आधारित प्रचार ऐप समाधान अपनाने पर विशेष जोर दिया। यह नई प्रणाली 01 अप्रैल 2026 से होर्डिंग्स और यूनिपोल्स के लिए लागू की जा चुकी है और जल्द ही इसे एलईडी स्क्रीन, ब्रांडिंग तथा डिजिटल वॉल पेंटिंग्स जैसे अन्य प्रारूपों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह प्रिंटिंग पर काफी शिकायतें सामने आ रही थीं, इन शिकायतों के कारण टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। नई प्रिंटिंग पॉलिसी यथा-शीघ्र लागू की जावेगी।

सशक्त नारी, समृद्ध परिवार : महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आत्मनिर्भरता का संबल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और उद्यमशीलता को भी नई दिशा दे रही है।

यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों महिलाएं इस योजना से प्राप्त राशि का उपयोग छोटे-छोटे व्यवसायों को शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में कर रही हैं। सरगुजा

जिले के अंबिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत थोर की शांतिपारा निवासी दुर्गा इसका एक उदाहरण हैं। लंबे समय से चूड़ी व्यवसाय से जुड़ी दुर्गा को पहले पूंजी की कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपये की सहायता ने उनके व्यवसाय को मजबूती दी है।

अब वे इस राशि का उपयोग अपने व्यवसाय की पूंजी बढ़ाने के साथ-साथ परिवार के दैनिक खर्चों में भी कर रही हैं। चार बच्चों की परवरिश करते हुए दुर्गा न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रही हैं।

प्रदेशभर में इस योजना के माध्यम से महिलाएं छोटे उद्यमों, घरेलू व्यवसायों और आजीविका गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। महतारी वंदन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है।

रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1.4 करोड़ की ठगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को साइबर ठगों ने 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इस दौरान उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव डाला और टेरर फंडिंग का डर दिखाकर घर से निकलने नहीं दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर महिला से 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए चार अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद भी ठगों का मन नहीं भरा और उन्होंने रिटायर्ड प्रोफेसर से 50 लाख की डिमांड की।

इसके अलावा उन्होंने बेटे और पोते को जेल भेजने की धमकी भी दी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में रहने वाले अपने बेटे को कॉल कर 50 लाख रुपए की मांग की और कहा कि पैसे भेज नहीं तो मैं जेल चली जाउंगी। तब जाकर ठगी की वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस रेंज साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

वाट्सएप पर आया था वीडियो कॉल

दरअसल के रियल हेवन निवासी प्रो. रमन श्रीवास्तव (82) रिटायर्ड प्रोफेस हैं। वे डीपी कॉलेज में पदस्थ थीं, उनका बेटा प्रशांत श्रीवास्तव मुंबई में एचआर कंसलटेंसी में डायरेक्टर हैं। 20 अप्रैल को उनके वाट्सएप पर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को संजय पीएसआई बताया।

वीडियो कॉल पर दो घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट

पहले उसने रिटायर्ड प्रोफेसर को धमकाया और कहा कि वह एक प्रतिबंधित संगठन (पीएफआई, पॉपुलर फ्रेंट ऑफइंडिया) को टेरर फंडिंग कर रही हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आया। वह डरी-सहमी रही। इस दौरान वीडियो कॉल पर ही 2 घंटे से ज्यादा समय तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा। फर्जी बैंक स्टेटमेंट और डेबिट कार्ड दिखाकर डराया

इस दौरान कथित अफसर ने रिटायर्ड प्रोफेसर को फर्जी दस्तावेज दिखाया, जिसमें उनके नाम का फर्जी बैंक स्टेटमेंट और डेबिट कार्ड था। कथित अफसर और ठग ने मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाते हुए उनका फोन टैप करने और किसी को बताने पर बेटे और पोते को भी मुंबई से गिरफ्तार करने की धमकी दी।

कथित अफसर ने रिटायर्ड प्रोफेसर के वाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट का वारंट सहित कई फर्जी दस्तावेज भी भेजे। साथ ही उनके खिलाफ वारंट जारी होने और गिरफ्तारी का डर दिखाया। साथ ही कहा कि उनके घर के लोकेशन के आसपास उनकी टीम तैनात है। ठग ने उन्हें बचने के लिए कहा कि हम जैसा कह रहे हैं, वैसा करना होगा।

डर के कारण रिटायर्ड प्रोफेसर ने न तो अपने बेटे को घटना की जानकारी दी और न ही पुलिस सूचित किया। इस दौरान एक सप्ताह तक वो किश्तों में पैसे देती रहीं। इस दौरान रिटायर्ड प्रोफेसर ने 21 अप्रैल को 20 लाख, 22 अप्रैल को 34.20 लाख रुपए, 23 अप्रैल को 15.20 लाख और 24 अप्रैल को 35.20 लाख रुपए ठग के बताए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी।

ठगों को देने बेटे से मांगी 50 लाख, तब खुला ठगी का राज

27 अप्रैल को ठग ने रिटायर्ड प्रोफेसर को ईडी का वारंट निरस्त होने का फर्जी लेटर भेजा, जिसके बाद केस पूरी तरह खत्म करने के लिए 50 लाख की और डिमांड की। लेकिन रिटायर्ड प्रोफेसर का बैंक अकाउंट खाली हो गया था। उनके पास पैसे ही नहीं थे।

इस पर उन्होंने मुंबई में अपने बेटे प्रशांत को कॉल किया। उन्होंने बेटे से कहा कि 50 लाख रुपए भेज नहीं तो मैं जेल चली जाउंगी। उनकी बातों को सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। मां की बातों को सुनकर प्रशांत ने पहले उन्हें संभाला और कहा कि मैं तुरंत बिलासपुर आ रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रशांत फ्लाइट से बिलासपुर पहुंचा और मां से पूछताछ की, तब ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद बेटे ने पुलिस अफसरों को मामले की जानकारी दी। इस पर रेंज साइबर थाना में केस दर्ज कराने कहा गया। रेंज साइबर पुलिस ने कथित आरोपी संजय पीएसआई के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

डिजिटल अरेस्ट के 8 मामले, अधिकतर में बुजुर्ग और रिटायर्ड कर्मचारी

ठगी के मामलों में ज्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी, बुजुर्ग और बड़े कारोबारी शिकार हो रहे हैं। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 57 लाख रुपए ठग लिए गए। इस मामले में रेंज साइबर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तोरवा और अन्य थाना क्षेत्रों में भी डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। इनमें एक मामला 1.31 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का भी है। रेंज साइबर थाने में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतों में करीब 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

खास खबर

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

कोरबा। शराब के नशे में बाइक खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मांगने पर पत्नी के मना कर देने पर जमीन पर पटक-पटककर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 11 नवंबर 2022 को हरदीबाजार चौकी क्षेत्र में हुई थी। हरदीबाजार में किराए का मकान लेकर पत्नी के साथ निवासरत धरम सिंह सिदार घटना दिनांक को शराब पीने के लिए पत्नी से 100 रुपए मांगकर ले गया था। नशे में घर लौटने के बाद ने उसने नई बाइक खरीदने के लिए पत्नी से 1 लाख रुपए की मांग की थी। पत्नी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर रजनी को जमीन पर गिरा दिया और पटक-पटककर उसकी हत्या कर दी। मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा की न्यायाधीश मधु तिवारी ने फैसला सुनाया।

बारात में हत्या करने वाला नाबालिग व उसका सहयोगी आरोपी गिरफ्तार हुआ

राजनांदगांव। डोंगरगढ़ के रामाटोला में बारात में युवक की हत्या करने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग आरोपी को धारदार चाकू उपलब्ध कराने वाले को भी पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। घटना 26 अप्रैल की रात हुई थी। रामाटोला में शादी के दौरान गांव में बारात निकली थी। तभी वहां योनिश सिन्हा डांस कर रहा था। तभी योनिश का पैर नाबालिग आरोपी को लग गया। इसके आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर उससे विवाद करने लगा और धारदार चाकू से योनिश पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले में दो लोग घायल भी हुए थे। डोंगरगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग और चाकू उपलब्ध कराने वाले सांकरा निवासी कृपाल वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

बारात में हंगामा, तीन लोगों का सिर फोड़ा, अपराध दर्ज

कोरबा। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात बारात में हंगामा मच गया। प्रारम्भिक जानकारी के मुताबिक अग्रसेन भवन से बारात निकली थी। इस दौरान जय स्तम्भ चैक के पास नरेंद्र ज्वेलर्स के सामने जाम लग गया था। बारात के बीच से रात करीब 10.30 बजे बाइक निकालने के दौरान हुए विवाद में दो युवक दाऊद अली व दानिश अली को बारातियों ने जमकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने हाथ-मुक्कों के साथ-साथ सड़क किनारे पड़े ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया। इस हमले में दोनों भाईयों के सिर पर गहरी चोटें आई हैं, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में 8 टांके लगाने पड़े। बारातियों ने इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक चालक पिंटू गुप्ता (निवासी चिरी, मध्य प्रदेश) के साथ भी मारपीट की। उसका भी माथा फूट गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घटना के बाद पीड़ितों ने कटघोरा थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए मामले की गंभीरता को देखते आरोपी अमित मित्तल, नितेश मित्तल एवं अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

कोरबा में दो दिन में 76 वारंटी गिरफ्तार

कोरबा। जिले में अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिनों में 76 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत चलाए गए विशेष अभियान में 50 गिरफ्तारी वारंट और 26 स्थायी वारंट तामील किए गए। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिलेभर में सघन दबिश दी गई। 27 और 28 अप्रैल को की गई कार्रवाई में लंबे समय से फरार आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी पहले से वारंट जारी होने के बावजूद फरार चल रहे थे। योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर इनकी गिरफ्तारी की गई।

मवेशी तस्कर ने किया सरेंडर: गिरफ्तारी से बचने छिप रहा था, पुलिस ने पहले उसके साथी को पकड़ा था

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मवेशी तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद शुरू किया है। लैलूंगा क्षेत्र के मवेशी तस्कर ने पुलिस की कार्रवाई से डरकर सरेंडर कर दिया है और आगे से तस्करी न करने की बात कही। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम करवाजोर का रहने वाला रब्बुल खान (39) लंबे समय से मवेशी तस्करी कर रहा था। उसके खिलाफ 2023 और 2026 में भी गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं।

फरवरी में उसके गिरोह के साथी देवानंद यादव को 16 मवेशियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय पूछताछ में रब्बुल खान का नाम सामने आया था।

इसके बाद से वह पुलिस से बचकर फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस की लगातार तलाश और ऑपरेशन शंखनाद के चलते उसके छिपने के सभी ठिकाने खत्म हो गए।

आखिरकार वह पकड़ा गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने आगे से मवेशी तस्करी न करने की बात भी कही है।

कार्रवाई लगातार जारी रहेगी

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लैलूंगा क्षेत्र के एक मवेशी तस्कर ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

उन्होंने कहा कि जो लोग अपराध छोड़ना चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन जो लोग तस्करी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

चौहान टाउन के फ्लैट में अचानक लगी आग

फर्स्ट फ्लोर में फैली आग, देर रात दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। भिलाई शहर के चौहान टाउन इलाके में बुधवार शाम एक फ्लैट में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि कमरे से लपटें और धुआं बाहर तक दिखाई देने लगा। हालांकि समय पर सूचना मिलने और दमकल टीम के तेजी से पहुंचने के कारण बड़ा हादसा टल गया।

घटना बुधवार रात की है। चौहान टाउन में स्थित कृष्णा कावरिया के प्रथम तल के फ्लैट में अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगी, वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दुर्ग अग्निशमन कार्यालय को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। कमरे में भर चुका था धुआं दमकल टीम के पहुंचने तक आग काफी फैल चुकी थी और पूरे कमरे में धुआं भर गया था। मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने बिना समय गंवाए तुरंत काम शुरू किया। टीम ने जोखिम उठाते हुए धुएं और आग से भरे फ्लैट के अंदर जाकर आग बुझाने का काम किया। दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में इसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग माना जा रहा है। इस घटना में किसी के घायल होने या जान-माल के बड़े नुकसान की खबर नहीं है। जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। उनके साथ सहायक प्रभारी प्रवीण बारा और दल प्रभारी केशव यादव व शरद मेश्राम मौजूद थे। टीम में धर्मेंद्र बंजारे, मोहन राव, राहुल, पवित्र, हरीश, मनोज, पराग और खेमराज जैसे कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर आग पर काबू पाया।

सड्डू में 55 साल के व्यक्ति की संदिग्ध मौत

घर से बदबू आने पर लोगों ने थाने में दी सूचना

श्रीकंचनपथ न्यूज

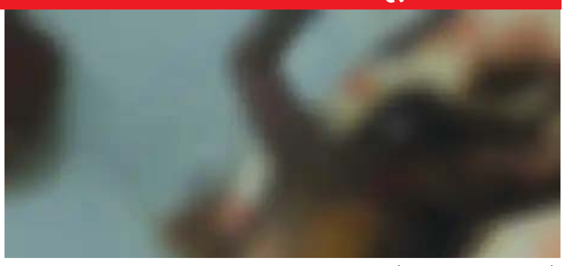

रायपुर। राजधानी रायपुर के सड्डू सेक्टर-7 स्थित एलआईजी-11 में सोमवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की पहचान योगेंद्र पाठक के रूप में हुई है, जो घर में अकेले रहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में टहलने के दौरान घर से तेज दुर्गंध आने लगी। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रायपुर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां कमरे में बेड पर योगेंद्र पाठक का शव पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे सामान्य मौत मान रही है, लेकिन मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। बताया जा रहा है कि मृतक का परिवार सड्डू के ही सेक्टर-3 में रहता है, जबकि वे अकेले इस मकान में रह रहे थे।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, भीषण गर्मी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मौत लू या अत्यधिक गर्मी के कारण हुई हो सकती है। फ्लिहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

रायगढ़ में सीनियर छात्र ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

घर में अकेली पाकर वारदात को दिया अंजाम, बदनाम करने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार आर्यन सोनी नामक सीनियर छात्र ने घर में अकेली पाकर वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी ने उसे फोन पर बदनाम करने की धमकी दी और गाली-गलौज भी की। पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आर्यन सोनी और उसके दोस्त पहले उनके घर आते-जाते थे। अक्टूबर 2025 में 16 साल बेटी घर पर अकेली थी, तो आर्यन सोनी ने उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नवंबर में भी उसने दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश की।

नाबालिग लड़की डर के कारण घटना के बारे में किसी को नहीं बता पाई। हालांकि आर्यन और उसके साथियों ने उसे लगातार फोन करके बदनाम करने और गाली-गलौज करने की धमकी दी।

इससे परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई। इसके बाद परिवार ने मिलकर महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(1),332(ठ), 351(4)बीएनएस और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। बुधवार को सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पीड़ित पक्ष पुलिस से सपर्क करें

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष निर्भीक होकर पुलिस से संपर्क करें। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

बच्चा चोरी की अफवाह, फेरीवाले की कर दी पिटाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

बस्तर। बस्तर के लोहंडीगुड़ा के बाजारपारा में बच्चा चोरी की आशंका ने तूल पकड़ लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश से आए फेरीवालों को घेरकर उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि अपनी जान बचाने के लिए फेरीवालों को एक घर के अंदर छिपना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर थाने पहुंचाया।

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले एक परिवार के सदस्य दो दिन पहले ही लोहंडीगुड़ा पहुंचे थे। वे किराए के मकान में रहकर गांव-गांव घूमकर फेरी का सामान बेच रहे थे। उनके घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान उनके साथ आए कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया, जिससे कुछ बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन एक बच्चा वहीं खड़ा रहा।

बच्चे को लेकर गलतफहमी फैली

बताया जा रहा है कि फेरीवाले उस बच्चे को वहां से जाने के लिए बार-बार कह रहे थे। इसी बीच बच्चे की एक रिश्तेदार ने यह देखा और बिना स्थिति को समझे बच्चा चोरी की आशंका जताते हुए गांव में यह बात फैला दी कि बाहर से आए लोग बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में यह बात पूरे गांव में फैल गई।

बिना पुष्टि के फेरीवालों पर हमला

देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। भीड़ ने बिना किसी पुष्टि के फेरीवालों को घेर लिया और गाली-गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थिति बेकाबू होती देख फेरीवालों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया।

घटना की सूचना मिलते ही लोहंडीगुड़ा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले भीड़ को शांत कराया, फिर घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर छिपे फेरीवालों को बाहर निकाला। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले जाया गया।

अफवाह निकली झूठी

वहीं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बच्चा चोरी की बात पूरी तरह अफवाह थी और फेरीवालों ने किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अफवाह फैलाने वालों के साथ-साथ मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा

रायपुर। रायपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर परिजनों को भेजने वाले मुख्य आरोपी सहित होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि टोनी ध्रुव उर्फमुन्नू शादी का झांसा देकर उसे जीई रोड स्थित एक होटल में ले गया। यहां अपने परिचित होटल मैनेजर की मदद से बिना वैध आईडी के कमरा लिया गया। इसके बाद आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाया और बाद में पीड़िता के परिजनों को भेज दिया। इसके बाद शादी से इनकार कर दिया। 24 घंटे में आरोपी और मैनेजर गिरफ्तार मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी और होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मैनेजर ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना आईडी प्रूफ के कमरा उपलब्ध कराया, जिससे अपराध में सहायता मिली।

पुलिस ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई-जिसमें केस दर्ज करने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक शामिल है-की जाएगी। शहर में समय-समय पर होटल-लॉज की जांच जारी रहेगी और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

बांगो हाईवे पर ट्रेलर चालक से लूट, दो आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। बांगो हाईवे पर प्रेशर कम होने पर रुके ट्रेलर चालक से लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार रात कटघोरा-अंबिकापुर के बीच बांगो हाईवे पर हुई थी, जहां गढ़वा निवासी वाहन चालक सलमान अंसारी कोयला लदा ट्रेलर लेकर अंबिकापुर से रायपुर जा रहा था। रात 2 बजे हसदेव नदी के पास ट्रेलर का प्रेशर कम होने पर उसने सड़क किनारे वाहन रोक दिया था। इस दौरान बिना नंबर वाले बोलेरो में 2 युवक उसके पास पहुंचे। उससे नकदी 78 सौ रुपए व मोबाइल से 17 सौ रुपए ट्रांसफर करा भाग गए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर रौनक सिंह (20) और कुनाल रजक (19) निवासी तिफरा-बिलासपुर को पकड़ा। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बोलेरो और लूटी गई रकम बरामद की।

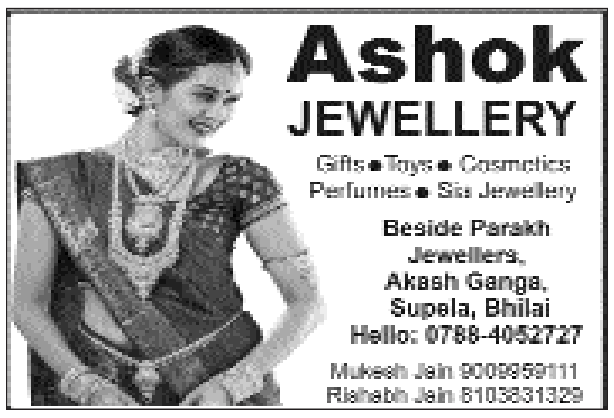

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950